Drishti IAS

# करेंट अफेयर्स राजस्थान

## जून (संग्रह)

## 2023

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

# अनुक्रम


**राजस्थान** **4**

- जयपुर में राज्य स्तरीय और जोधपुर व उदयपुर में संभाग स्तरीय मेलों का होगा आयोजन 4
- प्रदेश में तंबाकू फ्री यूथ कैंपेन का हुआ शुभारंभ 5
- 'स्टेट्स रिपोर्ट ऑन ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी इन अरबन टाउंस 2022-23' रिलीज़ 6
- खेल प्रतियोगिताओं में पदक विजेता राज्य कार्मिकों को मिलेगा स्पेशल इन्क्रीमेंट 7
- राजसमंद के गाँव मोलेला में बनेगा शिल्पग्राम 7
- जल जीवन मिशन कनेक्शन में राजस्थान 12वें स्थान पर 7
- मुख्यमंत्री नि:शुल्क बिजली योजना (घरेलू अनुदान) का बढ़ा दायरा 8
- वन मंत्री ने दिया 33 नये एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन सहित प्रदेश को कई सौगात 8
- राजस्थान उच्च न्यायालय और ज़िला न्यायपालिका के लिये नव विकसित ई-आर.टी.आई. पोर्टल का ई-उद्घाटन 9
- बाढ़ नियंत्रण के लिये कलक्टर ने नियुक्त किये इंसीडेंट कमांडर 11
- राजस्थान मंत्रिमण्डल की बैठक में लिये गए महत्त्वपूर्ण निर्णय 11
- मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना-2023 12
- आरटीडीसी में लागू होगी ओल्ड पेंशन स्कीम 13
- झालावाड़, बूंदी व बाँसवाड़ा में सिंचाई परियोजनाओं के लिये 156.13 करोड़ रुपए स्वीकृत 14
- 66वें नेशनल स्कूल गेम्स में चूरू की रितु कुमारी ने जीता शॉट पुट में ब्रोंज मेडल 14
- राजस्थान आवासन मंडल को मिले 4 और प्रतिष्ठित अवार्ड 15
- 66वें नेशनल स्कूल गेम्स में राजस्थान के दो खिलाड़ियों ने शतरंज में जीते गोल्ड मेडल 16
- राजस्थान किसान महोत्सव का जयपुर में होगा आयोजन 17
- अपर हाईलेवल केनाल परियोजना 18
- हरिदेव जोशी विश्वविद्यालय और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के बीच एमओयू 18
- 66वें नेशनल स्कूल गेम्स में राजस्थान ने जीते कुल 6 स्वर्ण, 12 रजत और 15 काँस्य पदक 20
- नोहर के रामपुरा पट्टी में 1.57 करोड़ की लागत से बनी नंदीशाला का हुआ लोकार्पण 21
- ज़िला स्तरीय रोड सेफ्टी टास्क फोर्स का होगा गठन 22
- राजस्थान साहित्य प्रोत्साहन पुरस्कार की होगी शुरुआत 22


**नोट :**

- मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना-2023 23
- प्रदेश में लोक कला विकास बोर्ड का होगा गठन 23
- पवन ऊर्जा के क्षेत्र में केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान प्रथम पुरस्कार से सम्मानित 24
- वन्य जीवों के संरक्षण हेतु 9 करोड़ रुपए स्वीकृत 24
- राजस्थान किसान महोत्सव 25
- विभिन्न ज़िलों के 441 गाँवों में खुलेंगे नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र 27
- एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड ने आईआईटी जोधपुर में अपनी पहली रूफटॉप सौर विद्युत परियोजना शुरू की 28
- जोधपुर में खुलेगा हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय 29
- धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये 13.48 करोड़ रुपए स्वीकृत 29
- कॉलेज में अध्ययनरत छात्राओं के लिये भी 'ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम' लागू 30
- प्रदेश में शोधार्थियों को मिलेगा आर्थिक संबल एवं प्रोत्साहन 30
- गोडवाड़ देसुरी में लेपर्ड कन्जर्वेशन रिजर्व होगा विकसित 30
- चिकित्सा मंत्री ने किया पीसीटीएस मोबाइल एप लॉन्च 31
- राजस्थान राज्य स्वर्ण रजत कला विकास बोर्ड का होगा गठन 32
- आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा को मिला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 32
- नीरज तंबोलिया 'राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड -2022' से सम्मानित 34
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने पालनहार फेस रिकॉग्निशन नवीनीकरण मोबाइल एप किया लॉन्च 34
- महिलाओं को अब रोडवेज की सभी श्रेणी की बसों में मिलेगी किराये में 50 प्रतिशत छूट 36
- टाईगर रिजर्व रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य में जंगल सफारी का हुआ शुभारंभ 36
- 13 शहरों में विकसित होंगे 'ग्रीन लंग्स' 37
- राजस्थान को मिला जैम एक्सीलेंसी अवार्ड 37
- मुख्य न्यायाधिपति ने 'आरएसएलएसए (रालसा) एट ए ग्लांस' पुस्तक का किया विमोचन 38
- 36 न्याय क्षेत्रों में होगी वल्नरेबल विटनस डिपोजिशन सेंटर्स की स्थापना 39
- 'डायल फ्यूचर' 40
- उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री ने कोयम्बटूर में राजस्थानी संघ भवन का उद्घाटन किया 41
- राजस्थान का एक स्टार्ट-अप यूथ को:लैब नेशनल इनोवेशन डायलॉग 2022 में विजेता बना 42
- जोधपुर एवं कोटा में स्थापित होंगे साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेंटर 43
- प्रदेश में तटरक्षक मेडल से अलंकृत सैनिकों को भी मिलेगा सुविधाओं का लाभ 43


नोट :

# राजस्थान

## जयपुर में राज्य स्तरीय और जोधपुर व उदयपुर में संभाग स्तरीय मेलों का होगा आयोजन

### चर्चा में क्यों ?

30 मई, 2023 को राजस्थान के कृषि एवं उद्यानिकी शासन सचिव डॉ. पृथ्वी की अध्यक्षता में पंत कृषि भवन में आयोजित किसान मेले की बैठक में शासन सचिव ने बताया कि जयपुर में राज्य स्तरीय और उदयपुर एवं जोधपुर में संभाग स्तरीय मेलों का आयोजन किया जाएगा।

### प्रमुख बिंदु

- शासन सचिव ने बताया कि जे.ई.सी.सी. सीतापुरा, जयपुर में राज्य स्तरीय मेले का आयोजन 16 से 18 जून तक किया जा रहा है। साथ ही 23 से 24 जून तक उदयपुर में एवं 30 जून एवं 01 जुलाई को जोधपुर में संभाग स्तरीय मेलों का आयोजन किया जा रहा है।
- राज्य स्तरीय मेले में 50 हज़ार और संभाग स्तरीय मेले में 20-20 हजार कृषक हिस्सा लेंगे।
- डॉ. पृथ्वी ने कहा कि राजस्थान में कृषि उत्पादकता और किसानों को नवीनतम तकनीकों से रूबरू करवाने के लिये राज्य सरकार कृषक मेलों का आयोजन कर रही है ताकि कृषि, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में लोगों को एक मंच पर लाया जा सके।
- कृषि आयुक्त कानाराम ने बताया कि तीन-दिवसीय मेले में नयी तकनीकें कृषकों को सिखायी जाएंगी जिससे कम लागत में अधिक आय प्राप्त हो सके और कृषक आर्थिक रूप से मजबूत बनें।
- कृषि आयुक्त ने कहा कि मेले का उद्देश्य किसानों को नवीनतम तकनीकी की जानकारी, आधुनिक कृषि पद्धतियों का प्रचार, कृषि क्षेत्र में नये विचारों और उद्यमशीलता समाधानों की प्रदर्शनी के लिये विभिन्न हितधारकों को मंच प्रदान करना एवं नये व्यवसायिक अवसरों और विकास के रास्ते तक पहुँच प्रदान करना है।

नोट :

# प्रदेश में तंबाकू फ्री यूथ कैंपेन का हुआ शुभारंभ

## चर्चा में क्यों ?

31 मई, 2023 को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के उपलक्ष्य में राजस्थान के झालाना स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में प्रदेशभर में तंबाकू फ्री यूथ कैंपेन का शुभारंभ किया गया।

## प्रमुख बिंदु

- कार्यक्रम में वर्ष 2022-23 में तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले झालावाड़, बारां, डूंगरपुर, अलवर, सीकर, चूरू, हनुमानगढ़ एवं अजमेर ज़िलों की तंबाकू नियंत्रण इकाइयों को सम्मानित किया गया।
- इस अवसर पर तंबाकू निषेध विषय से जुड़े पोस्टर एवं ब्रोशर का भी विमोचन किया गया।
- राज्य की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने कहा कि तंबाकू मुक्ति का यह अभियान निरोगी राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम है।
- उन्होंने तंबाकू नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु संचालित की जाने वाली 60 दिवसीय कार्ययोजना में शिक्षा, स्थानीय ग्रामीण एवं शैक्षणिक निकायों के साथ विभिन्न विभागों की सक्रिय सहभागिता पर बल दिया।
- इसके अलावा, उन्होंने इस कार्ययोजना के दौरान प्रदेश में शहरी व ग्रामीण वार्ड, ग्राम पंचायतों, शैक्षणिक संस्थानों को तंबाकू मुक्त करने के लिये प्रतियोगिता आयोजन जैसे नवाचार संचालित करने की आवश्यकता प्रतिपादित की।
- एनएचएम के मिशन निदेशक डॉ. जितेंद्र सोनी ने कहा कि एक वर्ष के भीतर शैक्षणिक संस्थानों को तंबाकू मुक्त बनाने एवं जनप्रतिनिधिगण के सहयोग से तंबाकू मुक्ति का प्रस्ताव करने की कार्ययोजना तैयार की जाएगी।

नोट :

# 'स्टेट्स रिपोर्ट ऑन ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी इन अरबन टाउंस 2022-23' रिलीज़

## चर्चा में क्यों ?

31 मई, 2023 को राजस्थान के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुबोध अग्रवाल ने अभियांत्रिकी विभाग के रसायनज्ञों की राज्य स्तरीय कार्यशाला में 'स्टेट्स रिपोर्ट ऑन ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी इन अरबन टाउंस ऑफ राजस्थान 2022-23' रिलीज़ की।

## प्रमुख बिंदु

- कार्यशाला में अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि वर्ष 2025-26 में प्रदेश के 1 करोड़ 7 लाख घरों में नल के माध्यम से पेयजल उपलब्ध होने लगेगा।
- प्रदेश के 235 शहरी क्षेत्रों का सर्वे इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिये किया गया है। 89 कस्बों में पेयजल आपूर्ति सतही जल स्रोतों से, 70 में सतही एवं भूजल दोनों से तथा 76 कस्बों में सिर्फ भूजल आधारित है।
- राज्य की समस्त 33 प्रयोगशालाएँ एन.ए.बी.एल. मान्यता प्राप्त हैं। इन प्रयोगशालाओं के एन.ए.बी.एल. सर्टिफिकेशन की निरंतरता के लिये यूनिसेफ एवं नीरी के सहयोग से समय-समय पर रसायनज्ञों एवं अन्य कार्मिकों के लिये प्रशिक्षण आयोजित किये गए हैं।
- स्टेटस रिपोर्ट तैयार करने में यूनिसेफ की ओर से पीएचईडी को तकनीकी सहयोग दिया गया।
- वाटर क्वालिटी पर तैयार स्टेटस रिपोर्ट का लाभ फील्ड अभियंताओं, रसायनज्ञों एवं अरबन प्लानिंग से जुड़े अधिकारियों को मिलेगा।
- जल जीवन मिशन के तहत समस्त परियोजनाएँ पूरी होने पर 2025 के अंत तक राजस्थान में 90 फीसदी पेयजल सतही स्रोतों से उपलब्ध होने लगेगा और भूजल पर निर्भरता 10 फीसदी रह जाएगी। प्रदेश में अभी 75 प्रतिशत योजनाओं में सतही स्रोतों की उपलब्धता है।
- जल जीवन मिशन के तहत मंज़ूर इन वृहद परियोजनाओं में राज्य सरकार की हिस्सा राशि 60 प्रतिशत जबकि केंद्र की 40 प्रतिशत होगी। इन परियोजनाओं के पूरी होने के बाद प्रदेश के 11 ज़िलों के 5739 गाँव भूजल से सतही जल आधारित योजनाओं पर आ जाएंगे।
- उल्लेखनीय है कि हाल ही में 23 हज़ार करोड़ रुपए की सतही जल आधारित पाँच बड़ी पेयजल परियोजनाओं को एसएलएसएससी की बैठक में मंज़ूरी मिली है।
- जल जीवन मिशन में केंद्र एवं राज्य सरकारों का उद्देश्य हर घर तक पीने योग्य पानी पहुँचाना है। मिशन के तहत हर घर तक जल पहुँचाने के लिये मौज़ूदा 130 करोड़ लीटर जल की ज़रूरत बढ़कर इसकी तीन गुना हो जाएगी।
- यूनिसेफ की स्टेट हैड इजाबेल बर्डम ने कहा कि वाटर हार्वेस्टिंग के लिये आधुनिक तकनीक के साथ ही परंपरागत जल संचय प्रणालियों का उपयोग किया जाएगा। कार्यशाला के माध्यम से पानी की गुणवत्ता के संबंध में भविष्य में आवश्यक कदम उठाने का रोडमैप तैयार हो सकेगा।

नोट :

## खेल प्रतियोगिताओं में पदक विजेता राज्य कार्मिकों को मिलेगा स्पेशल इन्क्रीमेंट

### चर्चा में क्यों ?

1 जून, 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजन एवं प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्य कार्मिकों को स्पेशल इन्क्रीमेंट वैयक्तिक वेतन के रूप में देने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे कार्मिकों को खेलों के प्रति प्रोत्साहन मिलेगा।

### प्रमुख बिंदु

- इसके लिये 1 अप्रैल, 2023 एवं इसके पश्चात् पात्र कार्मिकों को स्पेशल इन्क्रीमेंट के लिये खेल आयोजन के पूर्णता की दिनांक से 6 माह की अवधि में आवेदन करना होगा।
- कार्मिकों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने (पदक जीतने) पर क्रमश: 1 एवं 2 स्पेशल इन्क्रीमेंट वैयक्तिक वेतन के रूप में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर पर दिये जाएंगे।
- कार्मिक को पूरे सेवाकाल में अधिकतम 5 स्पेशल इन्क्रीमेंट ही मिलेंगे।
- स्पेशल इन्क्रीमेंट का लाभ खेल प्रतियोगिता की समाप्ति वाले माह के अगले माह की प्रथम दिनांक से देय होगा।

## राजसमंद के गाँव मोलेला में बनेगा शिल्पग्राम

### चर्चा में क्यों ?

1 जून, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मिट्टी से लोक देवी-देवताओं की मूर्तियाँ बनाने में अंतर्राष्ट्रीय पहचान रखने वाले राजसमंद ज़िले के खमनोर तहसील में स्थित मोलेला गाँव में शिल्पग्राम (शिल्पबाड़ी) की स्थापना व अन्य कार्यों के लिये 2.55 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है।

### प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री के इस निर्णय से मोलेला गाँव के शिल्पकर्मी अपनी कलाकृतियों का प्रदर्शन और बिक्री कर सकेंगे। वे यहाँ अपने कौशल से भावी पीढ़ियों को भी प्रशिक्षित कर सकेंगे। इससे युवाओं में कला के प्रति आकर्षण बढ़ेगा।
- शिल्पबाड़ी में सेमिनार हॉल, प्रदर्शनी हॉल, कैफेटैरिया व अन्य सुविधाएँ भी विकसित होंगी।
- विदित है कि मोलेला गाँव के मृण शिल्पकार लोक देवी-देवताओं का माटी में रूपांकन करते हैं। इन्हें मेवाड़ के साथ ही गुजरात व मध्य प्रदेश की सीमाओं के आदिवासी गाँवों के लोग खरीदते हैं। वे गाँव के देवघरों में इन्हें विधि-विधान से स्थापित कर धार्मिक परंपरा का निर्वाह करते हैं। इनकी खरीद अब घरों में सजावट के लिये भी हो रही है। बदलते परिवेश में कला प्रेमियों की इच्छाओं के अनुसार कलाकारों ने आधुनिक कलाकृतियाँ गढ़ना शुरू कर दिया है।
- ज्ञातव्य है कि टेराकोटा कला राजस्थान की प्रसिद्ध हस्तकलाओं में से एक है। लाल मिट्टी को पकाकर सजावटी सामान बनाने की कला टेराकोटा कला कहलाती है।
- मिट्टी की फड़ व मांदल नामक वाद्य यंत्र का निर्माण भी मोलेला गाँव में होता है।
- उल्लेखनीय है कि मोलेला गाँव के शिल्पकार देश-दुनिया में कला की छाप छोड़ चुके हैं। इन्हें पद्मश्री सहित अन्य राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी नवाजा जा चुका है।

## जल जीवन मिशन कनेक्शन में राजस्थान 12वें स्थान पर

### चर्चा में क्यों ?

4 जून, 2023 को राजस्थान के जलदाय मंत्री डॉ. महेश जोशी ने बताया कि जल जीवन मिशन में अभी तक कुल कनेक्शन का आँकड़ा 42.14 लाख को पार कर राजस्थान देश में 12वें स्थान पर पहुँच गया है।

नोट :

### प्रमुख बिंदु

- जलदाय मंत्री ने बताया कि जल जीवन मिशन में अभी तक 16 हज़ार 36 करोड़ रुपए खर्च कर व्यय के मामले में प्रदेश दूसरे स्थान पर पहुँच गया है। मिशन के तहत चालू वित्तीय वर्ष में अभी तक कुल 1521 करोड़ रुपए व्यय किये जा चुके हैं।
- उच्च स्तर पर निरंतर मॉनिटरिंग एवं समीक्षा से प्रदेश में मिशन का ग्राफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। राजस्थान ने अब तक के सर्वाधिक जल कनेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 31 मार्च को एक दिन में 27 हज़ार 470 कनेक्शन किये थे।
- वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 14 लाख 13 हज़ार 679 जल कनेक्शन किये जा चुके हैं। चालू वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही में कुल 4.75 लाख कनेक्शन का लक्ष्य है, जिसमें से 31 मई तक 3.05 लाख कनेक्शन हो चुके हैं।
- वित्तीय वर्ष 2022-23 के जल जीवन मिशन के तय लक्ष्यों को हासिल करने वाले श्रेष्ठ 5 ज़िलों में झालावाड़ ने 76 प्रतिशत, भीलवाड़ा ने 71, कोटा ने 69, चित्तौड़गढ़ ने 66 एवं उदयपुर ने 66 प्रतिशत प्रगति दर्ज की। प्रदेश में कुल 7 ज़िलों ने 50 फीसदी से अधिक जल कनेक्शन का लक्ष्य हासिल किया है।
- जलदाय मंत्री डॉ. महेश जोशी ने बताया कि जिस समय जल जीवन मिशन की शुरूआत हुई थी तब राजस्थान में महज 10 प्रतिशत जल कनेक्शन ही उपलब्ध थे। दिसंबर 2019 में प्रदेश में हर घर जल कनेक्शन वाले परिवारों की संख्या 11 लाख 74 हज़ार 131 थी, जो अब बढ़कर 42 लाख 14 हज़ार हो गई है।
- विदित है कि 2019 से लेकर अभी तक प्रदेश में 30 लाख 50 हज़ार नए जल कनेक्शन दिये जा चुके हैं, जो कि विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले राज्य के लिये एक उपलब्धि है।

## मुख्यमंत्री नि:शुल्क बिजली योजना ( घरेलू अनुदान ) का बढ़ा दायरा

### चर्चा में क्यों ?

2 जून, 2023 को राजस्थान के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को अधिक से अधिक राहत प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री नि:शुल्क बिजली योजना (घरेलू अनुदान) का दायरा बढ़ा दिया है।

### प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री नि:शुल्क बिजली योजना (घरेलू अनुदान) का दायरा बढ़ाने के तहत अब 100 यूनिट्स प्रतिमाह तक बिजली उपभोग करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं का बिजली बिल शून्य होने के साथ ही समस्त घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट्स प्रतिमाह से अधिक उपभोग होने पर भी पहले 100 यूनिट्स बिजली नि:शुल्क दी जाएगी।
- इसी प्रकार 200 यूनिट्स प्रतिमाह तक बिजली उपभोग करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं के पहले 100 यूनिट्स नि:शुल्क बिजली के साथ 200 यूनिट्स तक के स्थायी शुल्क, फ्यूल सरचार्ज एवं अन्य सभी शुल्क भी माफ होंगे।
- जयपुर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक आर. एन. कुमावत ने बताया कि इस योजना का लाभ बिलिंग माह जून, 2023 से दिया जाना है, जिसके लिये बिलिंग सॉफ्टवेयर में आवश्यक बदलाव किये जा रहे हैं।
- योजना के अनुसार बिलिंग सॉफ्टवेयर में आवश्यक बदलाव करने में 3 से 4 दिन का समय लगना संभावित है। इसके बाद ही घरेलू उपभोक्ताओं की माह जून, 2023 की बिलिंग शुरू कर दी जाएगी।
- उल्लेखनीय है कि 2000 यूनिट्स तक के उपभोग वाले कृषि उपभोक्ताओं को नि:शुल्क बिजली हेतु बिलिंग सॉफ्टवेयर में आवश्यक बदलाव करवाए जा चुके हैं। इसलिये घरेलू उपभोक्ताओं के अतिरिक्त अन्य सभी श्रेणी जैसे कृषि, औद्योगिक, वाणिज्यिक श्रेणी के उपभोक्ताओं की माह जून, 2023 की बिलिंग 4 जून से प्रारंभ की जा चुकी है।

## वन मंत्री ने दिया 33 नये एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन सहित प्रदेश को कई सौगात

### चर्चा में क्यों ?

5 जून, 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजस्थान के वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में 33 नये एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन का उद्घाटन तथा जमवारामगढ़ के थोलाई स्थित इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क का शिलान्यास किया।

नोट :

## प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर वन एवं पर्यावरण मंत्री ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति आमजन में चेतना लाने के उद्देश्य से जनजागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया तथा प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा पूर्व में आयोजित हैक द वेस्ट हैकाथॉन के विजेताओं को पुरस्कृत भी किया।
- वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी ने कहा कि आने वाली पीढ़ी के सुरक्षित भविष्य और प्रदूषण नियंत्रण के लिये सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंधित किया गया है। इसके साथ ही प्रदेश में जारी नवीन वन नीति में पौधारोपण को बढ़ावा दिया गया है।
- इस अवसर पर वन मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वैट लैंड और ग्रास लैंड विकास के लिये 40 करोड़ रुपए एवं विश्व प्रसिद्ध सांभर झील के विकास के लिये 10 करोड़ रुपए आवंटित किये हैं।
- उन्होने बताया कि प्रदेश में ईको टयूरिजम को बढ़ावा देने के लिये प्रत्येक ज़िले में 2-2 लव-कुश वाटिका का कार्य प्रगति पर है।
- इस अवसर पर राजस्थान ई-वेस्ट प्रबंधन नीति, राजस्थान जलवायु परिवर्तन नीति, राजस्थान वन नीति 2023, प्लास्टिक वेस्ट इंवेट्राइजेशन प्रतिवेदन सहित राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के ब्रोशर का विमोचन किया गया।

# राजस्थान उच्च न्यायालय और ज़िला न्यायपालिका के लिये नव विकसित ई-आर.टी.आई. पोर्टल का ई-उद्घाटन

## चर्चा में क्यों ?

5 जून, 2023 को राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने राजस्थान उच्च न्यायालय और ज़िला न्यायपालिका के लिये नव विकसित e-RTI Portal का वीडियो कांफ्रेन्सिग के माध्यम से उद्घाटन किया।

नोट :

## प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर मुख्य न्यायाधिपति ऑगस्टीन जार्ज मसीह ने कहा कि यह कदम पारदर्शी, कुशल और सुलभ न्यायिक प्रणाली को प्राप्त करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। पोर्टल से यह सुनिश्चित होगा कि आमजन का यह महत्त्वपूर्ण कानूनी अधिकार जटिल कागजी कार्यवाही और लंबी प्रक्रियाओं में ही उलझकर न रह जाए।
- इस अवसर पर मुख्य न्यायाधिपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़ द्वारा नवीनतम प्रौद्योगिकी के माध्यम से पूरी न्यायपालिका का कंप्यूटरीकरण और डिजीटलीकरण करने की चलाई जा रही मुहिम में इस पोर्टल को एक बढ़ता हुआ कदम बताया।
- राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के एग्जीक्यूटिव चेयरमेन न्यायाधिपति मनींद्र मोहन श्रीवास्तव ने इस अवसर पर कहा कि पोर्टल की सफलता न केवल तकनीकी कौशल पर बल्कि इसके प्रभावी उपयोग के लिये सामूहिक प्रतिबद्धता पर भी निर्भर करेगी। उन्होंने कहा कि यह पोर्टल देश के अन्य संस्थानों के लिये अनुकरणीय उदाहरण बनेगा।
- जोधपुर से विडियो कांफ्रेंसिग से जुड़े न्यायाधिपति अरुण भंसाली ने बताया कि यह पोर्टल न केवल आरटीआई आवेदन दाखिल करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करेगा बल्कि सूचना प्रसार की गति और सटीकता को भी बढ़ाएगा।
- उन्होंने कहा कि यह ऐसे एकल व केंद्रीकृत मंच के रूप में काम करेगा, जहाँ नागरिक अपने आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं, ऑनलाईन शुल्क जमा करा सकते हैं, आवेदन की स्थिति की जानकारी और समय पर सूचनाएँ भी प्राप्त कर सकते हैं।
- पूरी प्रक्रिया को डिजिटाइज करके, न केवल कागजी कार्रवाई की बाधाओं को समाप्त किया गया है बल्कि आवेदकों और सूचना प्रदाता अधिकारियों को एक सुरक्षित और सुविधाजनक चैनल भी प्रदान किया है।
- उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय ने रिट पिटीशन (सिविल) नंबर 1040/2019, प्रवासी लीगल सेल बनाम भारत संघ व अन्य मामले में सभी उच्च न्यायालयों व अधीनस्थ न्यायालयों के लिये सूचना के अधिकार के तहत ई-पोर्टल की क्रियान्विति के लिये निर्देश दिये थे, जिसकी अनुपालना में राजस्थान उच्च न्यायालय की तकनीकी टीम ने निर्देशों में दी गई अवधि से पूर्व ही ई-आर.टी.आई. पोर्टल और उससे संबंधित नियमों को मूर्त रुप प्रदान कर पोर्टल को लॉन्च किया है।
- ई-आर.टी.आई. पोर्टल का लिंक राजस्थान उच्च न्यायालय की अधिकारिक वेबसाईट के होम पेज पर सूचना के अधिकार के टेब में उपलब्ध कराया गया है।

नोट :

## बाढ़ नियंत्रण के लिये कलक्टर ने नियुक्त किये इंसीडेंट कमांडर

### चर्चा में क्यों ?

6 जून, 2023 को राजस्थान के जयपुर में आगामी मानसून सत्र में बाढ़ की संभावना को देखते हुए तथा बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिये एवं जल भराव के क्षेत्रों की मॉनिटरिंग करने के लिये ज़िला कलक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने इंसीडेंट कमांडर की नियुक्ति की है।

### प्रमुख बिंदु

- कलक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि शहरी क्षेत्र में 22 इंसीडेंट कमांडर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में भी उपखंड अधिकारियों को इंसीडेंट कमांडर की जिम्मेदारी सौंपी है। इंसीडेंट कमांडर संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर बाढ़ नियंत्रण एवं बचाव कार्य सुनिश्चित करेंगे।
- जयपुर महानगर में इंसीडेंट कमांडर नगर निगम जयपुर हैरिटेज/ग्रेटर एवं जयपुर विकास प्राधिकरण से समन्वय कर संसाधनों का आकलन करना एवं बाढ़ की स्थिति में राहत गतिविधियों का संचालन करेंगे।
- जल भराव की स्थिति में जल निकासी का प्रबंध करना, प्रभावित इलाकों में आवश्यक दवाईयों का छिड़काव करना, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में विद्यालय भवन, सामुदायिक भवन, आश्रय स्थल एवं पुनर्वास हेतु भवनों को चिन्हित करना एवं प्रभावित परिवारों को पुनर्वासित करवाना इंसीडेंट कमांडर्स की जिम्मेदारी होगी।
- कलक्टर ने बताया कि बाढ़ की स्थिति में ज़िला प्रशासन, पुलिस विभाग एवं सेना के साथ समन्वय कर आवश्यक इंतजाम सुनिश्चित किये जाएंगे।

## राजस्थान मंत्रिमण्डल की बैठक में लिये गए महत्त्वपूर्ण निर्णय

### चर्चा में क्यों ?

6 जून, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई, जिसमें कार्मिकों के हित में पदोन्नति, पेंशन, स्पेशल-पे, पदनाम के संबंध में महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गए।

### प्रमुख बिंदु

- मंत्रिमंडल ने राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इससे कार्मिक को 28 वर्ष की अर्हकारी सेवा के स्थान पर 25 वर्ष की सेवा पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने पर ही पूर्ण पेंशन का लाभ प्राप्त हो सकेगा।
- साथ ही, 75 वर्ष के पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर को 10 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन भत्ता प्राप्त हो सकेगा। कार्मिक/पेंशनर की मृत्यु की दशा में उसके विवाहित नि:शक्त पुत्र/पुत्री तथा 12,500 रुपए प्रतिमाह तक की आय वाले पात्र सदस्यों को भी पारिवारिक पेंशन का लाभ प्राप्त हो सकेगा। इस संशोधन की अधिसूचना दिनांक 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगी।
- मंत्रिमंडल ने राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इससे कार्मिकों के विशेष वेतन (स्पेशल-पे) में वृद्धि होगी।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2023-24 के बजट में इस संबंध में घोषणा की थी, जिसके अनुसार कर्मचारियों तथा अधिकारियों को वर्तमान में देय स्पेशल एलाउंस और स्पेशल पे में वेतन विसंगति परीक्षण समिति की अनुशंसा के अनुरूप वृद्धि किया जाना प्रस्तावित था।
- मंत्रिमंडल ने अब किसी भर्ती वर्ष में पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में इनकी रिक्तियाँ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग की तरह आगामी तीन वर्षों तक अग्रेषित करने का निर्णय लिया है। इससे इन वर्गों के अभ्यर्थियों को रोज़गार के अधिक अवसर प्राप्त हो सकेंगे।

नोट :

- मंत्रिमंडल ने राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 की अनुसूची-5 में संशोधन करते हुए वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों को पीजी डिग्री या समकक्ष डिप्लोमा होने पर अग्रिम वेतन वृद्धियों का पूर्ण लाभ देने का निर्णय किया गया है। इसमें वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी से उच्च पदों के लिये अग्रिम वेतन वृद्धियों का प्रावधान होने के कारण उच्च अधिकारियों को भी लाभ प्राप्त हो सकेगा।
- बैठक में राजस्थान अभियोजन सेवा (संशोधन) नियम, 2023 का अनुमोदन करते हुए अभियोजन सेवा के अधिकारियों को एक अतिरिक्त पदोन्नति का अवसर देने का निर्णय किया गया है।
- राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम- 1989, 1998, 2008 और 2017 में संशोधन कर कार्यप्रभारित कार्मिकों को नियमित कार्मिकों की तर्ज पर वेतनमान एवं पदनाम देने का निर्णय किया गया है।
- मंत्रिमंडल ने कार्मिक विभाग की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की रिक्तियों के आरक्षण के संबंध में 17.01.2013 को जारी अधिसूचना में राजस्थान मत्स्य राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम-2012, राजस्थान अधीनस्थ सेवा (भर्ती एवं अन्य सेवा शर्तें) नियम-2001, राजस्थान मदरसा शिक्षा सहायक अधीनस्थ सेवा नियम-2013 और राजस्थान विद्यालय सहायक अधीनस्थ सेवा नियम-2015 को शामिल करने का निर्णय किया है।
- मंत्रिमंडल ने आयुर्विज्ञान महाविद्यालय दौसा का नामकरण 'पं नवल किशोर शर्मा आयुर्विज्ञान महाविद्यालय दौसा' किये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 11 मई, 2023 को पंडित नवल किशोर शर्मा की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में इस संबंध में घोषणा की थी। पंडित नवल किशोर शर्मा का राजनीति के साथ-साथ खादी उद्योग के विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है।
- मंत्रिमंडल ने वीर गुर्जर विकास एवं धर्मार्थ ट्रस्ट, भीलवाड़ा तथा रैगर समाज, बीकानेर को भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है।

## मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना-2023

### चर्चा में क्यों ?

7 जून, 2023 को राजस्थान के कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्त्व मंत्री डॉ. बीडी कल्ला की अध्यक्षता में 'मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना-2023' के सफल क्रियान्वयन के संबंध में बैठक आयोजित की गई, जिसमें योजना से संबंधित जानकारी दी गई।

### प्रमुख बिंदु

- संस्कृति एवं पुरातत्त्व मंत्री ने कहा कि बजट घोषणा 2023-24 के क्रम में विभाग ने इस योजना का प्रारूप तैयार किया है।
- मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा अनुरूप 'मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना-2023' के अंतर्गत राजस्थान के स्थानीय या देशज कला के कलाकारों को 100 दिन का रोज़गार दिया जाएगा।
- स्थानीय कलाकारों को 100 दिन का रोज़गार सुनिश्चित कराने वाला राजस्थान संभवत: देश में पहला प्रदेश है। ये कलाकार गायन, वादन, नृत्य, अभिनय या नाटक करने वाले होंगे जो राज्य सरकार के कार्यक्रमों, उत्सवों में 100 दिन के कला प्रदर्शन की मांग कर सकेंगे।
- योजना के सफल क्रियान्वयन के लिये राजस्थान संगीत नाटक अकादमी को नोडल एजेंसी बनाया गया है।
- राजस्थान नाटक संगीत अकादमी की अध्यक्षा बिनाका जेश मालू ने बताया कि अकादमी योजना के माध्यम से लोक कलाकारों के कल्याण के लिये प्रतिबद्ध है। योजना के गाँव-ढाणी से कस्बों तक सफल क्रियान्वयन के लिये पूरी तैयारी कर ली गई है।
- कला एवं संस्कृति विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री ए. राठौड़ ने एक प्रस्तुतिकरण के माध्यम से योजना की अद्यतन प्रगति और प्रारूप में लोक कलाकारों द्वारा आवेदन पत्र, प्रक्रिया और भुगतान सहित महत्त्वपूर्ण जानकारी से मंत्री को अवगत कराया।

नोट :

# आरटीडीसी में लागू होगी ओल्ड पेंशन स्कीम

## चर्चा में क्यों ?

7 जून, 2023 को जयपुर के पर्यटन भवन में आयोजित राजस्थान पर्यटन विकास निगम बोर्ड (आरटीडीसी) की 192वीं बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा की गई बजट घोषणा की अनुपालना में अब आरटीडीसी के कार्मिकों को भी ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ देने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

## प्रमुख बिंदु

- आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने कहा कि निगम प्रबंधन प्रदेश में पर्यटन सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिये प्रतिबद्ध है तथा आरटीडीसी की होटल इकाइयाँ एवं पैलेस ऑन व्हील्स मुनाफे के साथ संचालित हो रही हैं।
- निजी होटल्स से प्रतिस्पर्धा के लिये 10 आरटीडीसी होटल इकाइयों में जीर्णोद्धार एवं उन्नयन के कार्य प्रगतिरत हैं।
- राजस्थान वेडिंग एंड कॉन्फ्रेंस डेस्टिनेशन के रूप में देश के एक प्रमुख राज्य के रूप में अपनी जगह बना चुका है। एमआईसीई (मीटिंग्स, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस एंड एक्जीबिशंस) सेंटर्स की स्थापना से प्रदेश को इस क्षेत्र में एक नई पहचान मिलेगी।
- बैठक में आरटीडीसी होटल्स के शुल्क में छूट की श्रेणी में राजस्थान रत्न से सम्मानितों को शामिल करने के प्रस्ताव पर भी निर्णय लिया गया। साथ ही, अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों में शिथिलता देने पर चर्चा हुई।

नोट :

## झालावाड़, बूंदी व बाँसवाड़ा में सिंचाई परियोजनाओं के लिये 156.13 करोड़ रुपए स्वीकृत

### चर्चा में क्यों ?

8 जून, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में सिंचाई तंत्र को सुदृढ़ बनाने हेतु जल संसाधन विभाग से संबंधित 5 विकास कार्यों हेतु 156.13 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी है।

### प्रमुख बिंदु

- इस राशि से झालावाड़ ज़िले में राजगढ़ मध्यम सिंचाई परियोजना में फव्वारा पद्धति के विकास कार्य, घुघवा लघु सिंचाई परियोजना में निर्माण कार्य तथा गागरीन सिंचाई परियोजना में आवश्यक सिंचाई सुविधा के कार्य कराए जाएंगे।
- इसके साथ ही बूंदी ज़िले में उतराना माइक्रो लिफ्ट सिंचाई परियोजना में निर्माण कार्य तथा बाँसवाड़ा ज़िले के कूपड़ा गाँव में अनास नदी पर एनिकट का निर्माण कराया जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने वर्ष 2023-24 के राज्य बजट में इस संबंध में घोषणा की थी।

## 66वें नेशनल स्कूल गेम्स में चूरू की रितु कुमारी ने जीता शॉट पुट में ब्रोंज मेडल

### चर्चा में क्यों ?

8 जून, 2023 को राजस्थान के चूरू ज़िले की रितु कुमारी ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित हो रहे 66वें नेशनल स्कूल गेम्स में शॉट पुट स्पर्धा में काँस्य पदक जीता है।

### प्रमुख बिंदु

- रितु कुमारी ने शॉट पुट स्पर्धा में 13.28 मीटर गोला फेंककर 19 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 117 खिलाड़ियों के बीच प्रदेश को ब्रोंज मैडल दिलाया।
- इसके अलावा अलग-अलग भार वर्गों में जोधपुर एवं उदयपुर ज़िलों के पाँच मुक्केबाजों ने सेमीफाईनल में प्रवेश कर प्रदेश के खाते में और पदकों की उम्मीद जगाई है।
- विदित है कि राज्य के खिलाड़ियों ने अब तक इन खेलों में दो गोल्ड, दो सिल्वर और एक काँस्य पदक जीते हैं।
- उल्लेखनीय है कि 66वें नेशनल स्कूली गेम्स में भोपाल, ग्वालियर और नई दिल्ली में आयोजित हो रही विविध खेल स्पर्धाओं में राजस्थान के स्कूल शिक्षा विभाग के बैनर तले प्रदेश के खिलाड़ी व्यक्तिगत और टीम स्पर्धाओं में शिरकत कर रहे हैं।
- भोपाल में ही चल रहे बॉक्सिंग मुकाबलों में छात्राओं के 45-48 किलोग्राम भार वर्ग में जयपुर की यामिनी कंवर (राजा रामदेवी पोद्दार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गांधी नगर, जयपुर), छात्रों के 52-56 किलोग्राम भार वर्ग में उदयपुर के आमिल अली (राजकीय फतेह उच्च माध्यमिक विद्यालय, उदयपुर), 60-64 किलोग्राम भार वर्ग में जोधपुर के संकल्प लवानिया (श्री केके मॉडर्न उच्च माध्यमिक विद्यालय, जोधपुर), 64-69 किलोग्राम वर्ग में जोधपुर के रितिक सिवाच (वंदना पब्लिक अकादमी, प्रताप नगर, जोधपुर) तथा 69-75 किलोग्राम वर्ग में जोधपुर के ही अमन घिटेला (न्यू सेंट्रल अकादमी, जोधपुर) ने सेमीफाईनल में प्रवेश कर प्रदेश के लिये पदकों की संभावनाएँ जगाई हैं।

नोट :

## राजस्थान आवासन मंडल को मिले 4 और प्रतिष्ठित अवार्ड

### चर्चा में क्यों ?

10 जून, 2023 को दिल्ली स्थित एपी शिंदे सिंपोजियम में आयोजित भव्य समारोह में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को 4 राष्ट्रीय स्तर के अवार्ड प्राप्त हुए।

### प्रमुख बिंदु

- शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार की इकाई आईबीसी (इंडियन बिल्डिंग्स कांग्रेस) ने मंडल के 4 प्रोजेक्ट्स को एक्सीलेंस इन बिल्ट एनवायरनमेंट के लिये सम्मानित किया।
- राज्य के सिटीपार्क, कोचिंग हब, चौपाटी और शिक्षक प्रहरी आवास योजना इससे पूर्व भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खासी चर्चित रह चुके हैं। टिकट लगने के बावजूद सिटी पार्क में प्रतिदिन हज़ारों की संख्या में स्थानीय और विदेशी पर्यटक इसकी खूबसूरती का दीदार करने आते हैं।
- प्रताप नगर और मानसरोवर में स्थापित चौपाटी के लजीज क्यूजीन और व्यंजनों के तो शहरवासी दीवाने हैं। चौपाटियों के शुरुआती 5 महीनों में अधिकतम फुटफाल के लिये दो अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड भी मिल चुके हैं। चौपाटियों पर चलने वाला लाइव बैंड आगंतुकों के खास आकर्षण का केंद्र रहा है।
- प्रताप नगर में बना कोचिंग हब देश का पहला ऐसा संस्थान है, जहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त भवन में निजी कोचिंगें एक साथ संचालित होने को हैं।
- इनके अलावा प्रदेश में शिक्षक और कांस्टेबल के लिये पहली बार बनी आवास परियोजना रही, जहाँ रहवासियों को स्विमिंग पूल, स्पोर्ट्स अरेना, कम्युनिटी एरिया, लैंड स्कैपिंग तथा अन्य सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई।
- गौरतलब है कि आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा की अगुवाई में पिछले चार वर्षों में मंडल को कुल 21 अवार्ड मिल चुके हैं।
- इनमें मकान विक्रय में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, स्कॉच अवार्ड-2021, अवार्ड ऑफ एक्सीलेंसी, नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा सम्मान, नेशनल हाउसिंग अवार्ड, आई.बी.सी और 'स्टार ऑफ गवर्नेंस-गोल्ड अवार्ड'और नरेडको द्वारा दिये 'रियल एस्टेट कॉन्क्लेव'जैसे प्रतिष्ठित अवार्ड शामिल हैं।
- उल्लेखनीय है कि शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के समर्थन से स्थापित यह निकाय हर साल विभिन्न श्रेणियों के भवनों में 'निर्मित पर्यावरण में उत्कृष्टता'(एक्सीलेंस इन बिल्ट एनवायरनमेंट) के लिये आईबीसी अवार्ड प्रदान करता है।

नोट :

## 66वें नेशनल स्कूल गेम्स में राजस्थान के दो खिलाड़ियों ने शतरंज में जीते गोल्ड मेडल

### चर्चा में क्यों ?

10 जून, 2023 को 66वें नेशनल स्कूली गेम्स में नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में खेले गए शतरंज के मुकाबलों में राजस्थान के स्कूली शिक्षा विभाग की टीम के दो खिलाड़ी उदयपुर के प्रणय चोर्डिया एवं बीकानेर की युक्ति हर्ष ने व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीतकर प्रदेश को गौरवान्वित किया।

### प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है राजस्थान में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी विद्यालयों में 'नो बैग डे' और 'चैस इन स्कूल'एक्टिविटीज के नवाचार लागू किये गए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री स्व. इंदिरा गांधी की जयंती (19 नवंबर, 2022) पर प्रदेशभर में 'चैस इन स्कूल एक्टिविटी'के तहत सरकारी विद्यालयों के 38 लाख 21 हज़ार 9 विद्यार्थियों ने भाग लिया था, जिसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकार्ड्स में भी दर्ज किया गया।
- नेशनल स्कूल गेम्स में पहली बार भाग लेने गई प्रदेश की टीम के लिये प्रणय चोर्डिया और युक्ति हर्ष की शतरंज में स्वर्णिम चालों को इन नवाचारों से जोड़कर देखा जा सकता है।
- प्रणय चोर्डिया ने जहाँ प्रथम बोर्ड पर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए सभी छः राउंड की बाजियों में अपने प्रतिद्वंद्वियों को मात देकर पूरे छः अंक हासिल किये, वहीं युक्ति हर्ष ने पाँच बाजियों में से तीन में जीत और दो ड्रा के साथ 4 अंक अर्जित करते हुए व्यक्तिगत स्तर पर स्वर्ण पदक जीतने में सफलता प्राप्त की।

नोट :

## राजस्थान किसान महोत्सव का जयपुर में होगा आयोजन

### चर्चा में क्यों ?

10 जून, 2023 को राजस्थान के कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने बताया कि राज्य में कृषि उत्पादकता बढ़ाने और किसानों को नवीनतम तकनीकों से रूबरू करवाने के लिये राज्य सरकार द्वारा 16-18 जून को जयपुर के सीतापुरा में जे.ई.सी.सी. में 'राजस्थान किसान महोत्सव'का आयोजन किया जाएगा।

### प्रमुख बिंदु

- कृषि, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में लोगों को एक मंच पर लाने और कृषि एवम संबंधित क्षेत्रो में समावेशित विकास सुनिश्चित करने के लिये इस तरह के मेलों की महत्त्वपूर्ण भूमिका है।
- 'राजस्थान किसान महोत्सव'के अलावा 23-24 जून को उदयपुर एवं 30 जून और 01 जुलाई को जोधपुर में संभाग स्तरीय किसान मेलों का आयोजन किया जाएगा। राज्य स्तरीय किसान मेले में 50 हज़ार और संभाग स्तरीय मेले में 20-20 हज़ार किसान हिस्सा लेंगे।
- कृषि मंत्री ने बताया कि मेले में नयी कृषि तकनीकें किसानों को सिखाई जाएंगी, जिससे कम लागत में अधिक आय प्राप्त हो सके और किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत बन सके।
- किसान महोत्सव में स्मार्ट फार्म, कृषि, बागवानी, पशुपालन, डेयरी, मत्स्यपालन व कृषि विपणन की विश्वस्तरीय तकनीकों का प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही, कृषि उत्पाद, औजार, बीज आदि की वृहद प्रदर्शनी लगाई जाएगी, एवं अत्याधुनिक कृषि मशीनरी का प्रदर्शन भी किया जाएगा।
- मेले में किसानों के लिये जाजम चौपाल भी रखी गई है जिसमें किसान विषय विशेषज्ञों से संवाद कर सकेंगे। कार्यक्रम में किसानों के लिये विषयवार सेमिनार और कृषक गोष्ठियों का कार्यक्रम भी रखा गया है।
- मेले में युवाओं को इंटरप्रेन्योर बनाने के लिये कृषि स्टार्ट-अप्स से मुलाकात करवाई जाएगी, जिससे युवा कृषि के क्षेत्र में उद्यमी बनकर नए रोज़गारों का सृजन कर सकेंगे। मेले में मनोरंजन का विशेष ध्यान रखा जाएगा। इसके लिये फिल्म, साहित्य व सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखे जाएंगे।

नोट :

## अपर हाईलेवल केनाल परियोजना

### चर्चा में क्यों ?

12 जून, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के बाँसवाड़ा ज़िले के लंकाई (बागीदौरा) में अपर हाई लेवल केनाल परियोजना के अंतर्गत अनास नदी पर साइफन निर्माण और मगरदा में 2500 करोड़ रुपए की अपर हाई लेवल केनाल परियोजना का शिलान्यास किया।

### प्रमुख बिंदु

- अपर हाई लेवल केनाल परियोजना से ज़िले की 6 तहसीलों बाँसवाड़ा, बागीदौरा, गांगड़ तलाई, आनंदपुरी, कुशलगढ़ और सज्जनगढ़ को जोड़ा गया है। इससे 338 गाँवों के 42 हज़ार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।
- यहाँ माही परियोजना के बांध से 105 किमी. लंबी मुख्य नहर का निर्माण होगा। मुख्य नहर से वितरिका और माइनर निकालकर डिग्गी निर्माण कर फव्वारा पद्धति द्वारा सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसका कार्य नवंबर, 2026 तक पूर्ण किया जाना है। इसमें 210 डिग्गियाँ और 4 किमी. लंबी टनल भी बनेगी।
- इस परियोजना में अनास नदी पर एक साइफन बनाया जा रहा है। यह गांगड़ तहसील के लंकाई गाँव में स्थित है। यह साइफन परियोजना की एक महत्त्वपूर्ण संरचना है। इसमें मुख्य नहर को अनास नदी के नीचे से प्रेशराइज पाइपलाइन द्वारा निकालना प्रस्तावित है।
- केनाल परियोजना आदिवासी अंचल की महत्त्वाकांक्षी परियोजना है। इससे सिंचाई जल सुनिश्चितता के चलते क्षेत्र में सतत् रूप से विकास संभव हो सकेगा और रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे। यह परियोजना अंचल के सामाजिक-आर्थिक उत्थान में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बाँसवाड़ा ज़िले की ग्राम पंचायत छोटी सरवा को पंचायत समिति में क्रमोन्नत करने की घोषणा भी की।

## हरिदेव जोशी विश्वविद्यालय और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के बीच एमओयू

### चर्चा में क्यों ?

12 जून, 2023 को जयपुर में स्थित हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय (एचजेयू) के प्रशासनिक परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम में एचजेयू और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) ने मीडिया के विभिन्न क्षेत्रों की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों में स्वास्थ्य, जेंडर और सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों की समझ बढ़ाने के लिये एक एमओयू किया।

नोट :

## प्रमुख बिंदु

- यूएनएफपीए की कंट्री हेड एंड्रिया वोयनार और एचजेयू की कुलपति प्रो. सुधि राजीव ने एमओयू पर हस्ताक्षर किये।
- विदित है कि यूएनएफपीए संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है जो जेंडर, महिला एवं बाल अधिकारों और स्वास्थ्य के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र के सतत् विकास लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में काम करती है। यह बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान स्थित अपने मुख्यालयों के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर विकास कार्यों में सहभागिता निभाती है।
- इस अवसर पर यूएनएफपीए की कंट्री हेड एंड्रिया वोयनार ने कहा कि एचजेयू के साथ एमओयू से जेंडर संबंधी मुद्दों की समझ रखने वाले बेहतरीन पत्रकार तैयार करने में मदद मिलेगी। जब ये विद्यार्थी मीडिया का हिस्सा बनेंगे तो इन मुद्दों को बेहतर तरीके से रख सकेंगे और इससे संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास लक्ष्यों को हासिल करने में मदद मिलेगी।
- यूएनएफपीए की कंट्री हेड ने बताया कि वे अपने 10वें राष्ट्रीय कार्यक्रम (2023-2027) के दौरान यूएनएफपीए मातृत्व मृत्यु दर में कमी, परिवार नियोजन, जेंडर आधारित हिंसा को खत्म करने और अन्य मानवीय स्थितियों में सुधार के लिये प्रयासरत है।
- समझौते के तहत विद्यार्थियों के लिये लैंगिक मुद्दों, जनसांख्यिकी और किशोरों के स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर प्रशिक्षण सत्र आयोजित किये जाएंगे।
- एचजेयू की कुलपति प्रो. सुधि राजीव ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यिवस्था में सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाना मीडिया की जिम्मेदारी है। ऐसे में भावी पत्रकारों में जेंडर, महिला एवं बाल विकास से जुड़े मुद्दों के प्रति चेतना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूएनएफपीए और एचजेयू का यह समझौता सामाजिक मुद्दों के प्रति जागरूक और जिम्मेदार मीडियाकर्मी तैयार करने की दिशा में अहम कदम साबित होगा।

नोट :

# 66वें नेशनल स्कूल गेम्स में राजस्थान ने जीते कुल 6 स्वर्ण, 12 रजत और 15 काँस्य पदक

## चर्चा में क्यों ?

13 जून, 2023 को समाप्त हुए 66वें नेशनल स्कूल गेम्स की टीम और व्यक्तिगत खेल स्पर्धाओं में राजस्थान के खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से धूम मचाते हुए राजस्थान के लिये 6 स्वर्ण, 12 रजत और 15 काँस्य पदक जीते ।

## प्रमुख बिंदु

- 66वें नेशनल स्कूल गेम्स के अंतिम दिन नई दिल्ली में टेनिस में टीम इंवेंट में जयपुर की सानिया खान ने व्यक्तिगत स्पर्धा में भी रजत पदक जीतकर प्रदेश को गौरवान्ति किया। वहीं, भोपाल में जूडो में श्रीगंगानगर जिले की लावण्या अरोड़ा ने काँस्य पदक जीता, जो जूडो में राजस्थान का पाँचवाँ पदक था।
- नेशनल स्कूल गेम्स में प्रदेश ने पहली बार टीम स्पर्धा में देश में दूसरा स्थान प्राप्त करते हुए रजत पदक जीता।
- शतरंज में अपने-अपने बोर्ड पर व्यक्तिगत तौर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए उदयपुर के प्रणय चोर्डिया और बीकानेर की युक्ति हर्ष ने गोल्ड मेडल अपने नाम किये, ये दोनों मेडल प्रदेश को मिले 6 स्वर्ण पदकों के अलावा है।
- बीकानेर के केशव बिस्सा ने वेट लिफ्टिंग में प्रदेश के लिये गोल्ड मेडल दिलाने के साथ ही प्रतियोगिता के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनने का भी श्रेय हासिल किया।
- राजस्थान के लिये नागौर की कविता डूडी ने 3000 मीटर रेसवॉक, चुरू की नीतू कुमारी एवं सुमित कुमार ने डिस्कस थ्रो, भीलवाड़ा की माया माली ने कुश्ती और जयपुर की ताश्री मेनारिया ने बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीते।
- इसके अलावा प्रदेश के खिलाड़ियों ने बैडमिंटन, हॉकी, वालीबॉल और ताइक्वांडो सहित अन्य खेलों में भी अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया।

नोट :

# नोहर के रामपुरा पट्टी में 1.57 करोड़ की लागत से बनी नंदीशाला का हुआ लोकार्पण

## चर्चा में क्यों ?

13 जून, 2023 को राजस्थान के खान पेट्रोलियम एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया तथा स्थानीय विधायक अमित चाचाण ने प्रदेश के हनुमानगढ़ ज़िले के नोहर स्थित रामपुरा पट्टी श्री गौशाला में 1.57 करोड़ की लागत से बनी नंदीशाला का लोकार्पण किया।

## प्रमुख बिंदु

- विदित है कि प्रदेश में आवारा नंदियो की समस्या को देखते हुए पंचायत स्तरीय नंदीशाला योजना की घोषणा की गई और इसे क्रियान्वित करते हुए पंचायत समिति स्तर पर नंदी शालाओं का संचालन किया जा रहा है।
- गोपालन मंत्री ने कहा कि गोपालन में आ रही समस्याओं का समाधान करने हेतु मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में गौशाला संचालकों के सुझाव के आधार पर अनुदान की प्रक्रिया को सरल बनाया गया। जहाँ पहले पंजीयन के लिये 200 पशु तथा 2 साल का गौशाला संचालन का अनुभव आवश्यक था, वहीं इस प्रक्रिया को आसान करते हुए 100 पशु और 1 साल का संचालन अनुभव निर्धारित किया गया है।
- छोटे पशुओं के लिये जो अनुदान पहले 16 रुपए था, उसे बढ़ाकर 20 रुपए किया गया तथा बड़े पशुओं के लिये जो अनुदान पहले 32 रुपए था उसे बढ़ाकर 40 रुपए किया गया। अब बीमार गौवंश तथा नंदी गौवंश के लिये अनुदान 12 माह के लिये दिया जा रहा है।
- गोपालन मंत्री ने राज्य सरकार की 5 वर्ष की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि पिछले साढ़े चार वर्षों में गौशालाओं को 2700 करोड़ अनुदान राशि का भुगतान किया गया। राजस्थान देश में पहला राज्य है जहाँ गौशालाओं के लिये इतना बजट खर्च किया जा रहा है।
- उन्होंने कहा कि गौशालाओं को प्रति वर्ष 1200 से 1400 करोड़ रुपए का अनुदान की स्थिरता प्रदान होगी। पशुपालकों को संबल प्रदान करते हुए दूध उत्पादन पर जहाँ पहले 2 रुपए अनुदान था, उसे बढ़ाकर अब 5 रुपए किया गया। अब तक प्रदेशभर में 400 करोड़ रुपए से अधिक की संबल राशि प्रदान की जा चुकी है।

नोट :

## ज़िला स्तरीय रोड सेफ्टी टास्क फोर्स का होगा गठन

### चर्चा में क्यों ?

13 जून, 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम उठाते हुए विभिन्न विभागों के अधिकारियों को सम्मिलित करते हुए ज़िला स्तर पर रोड सेफ्टी टास्क फोर्स के गठन को मंजूरी दी है।

### प्रमुख बिंदु

- परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग ज़िला सड़क सुरक्षा टास्क फोर्स का प्रशासनिक विभाग होगा।
- संबंधित ज़िले के ज़िला कलक्टर की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन होगा। इसमें ज़िला पुलिस अधीक्षक, ज़िला परिषद् के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, ज़िला मुख्यालय के नगरीय निकाय के आयुक्त शामिल होंगे।
- इनके अलावा सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता, ज़िला मुख्यालय के विकास प्राधिकरण/नगर विकास न्यास के सचिव, स्वायत्त शासन विभाग के अधिशाषी अभियंता, माध्यमिक शिक्षा के मुख्य ज़िला शिक्षा अधिकारी, ज़िला अस्पताल के अधीक्षक/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, एन.आई.सी के सदस्य, एनएचएआई के परियोजना निदेशक तथा आईरेड/ई-डार प्रतिनिधि सदस्य होंगे।
- सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में कार्यरत एक गैर–सरकारी संस्था के विशेषज्ञ प्रतिनिधि तथा दो सड़क सुरक्षा सलाहकार इस टास्क फोर्स में विशेष आमंत्रित एवं ज़िला/प्रादेशिक परिवहन अधिकारी सदस्य सचिव होंगे।
- ज़िला कलक्टर टास्क फोर्स की बैठक में किसी भी संबंधित विभाग के प्रतिनिधि को आमंत्रित तथा फोर्स के कार्यों के लिये निर्देशित कर सकेंगे।
- टास्क फोर्स के कार्य :
  - प्रत्येक 3 माह में टास्क फोर्स की कम से कम एक बार बैठक आयोजित होगी। ज़िला सड़क सुरक्षा टास्क फोर्स ज़िले में सड़क दुर्घटनाओं एवं उनसे होने वाली मृत्यु दर में वर्ष 2030 तक 50 प्रतिशत की कमी लाने के लिये वार्षिक कार्य योजना की प्रभावी क्रियान्विति, समिति के निर्णयों की क्रियान्विति सुनिश्चित करेगा।
  - इसके अलावा यह नियमित पर्यवेक्षण, सड़क सुरक्षा ऑडिट करवाकर ऑडिट अनुशंसाओं की समयबद्ध पालना, उच्चतम न्यायालय सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशों की अनुपालना, सड़क सुरक्षा से संबंधित राज्य की योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार, जन जागरुकता अभियान का आयोजन तथा पूरे साल विशेष प्रवर्तन अभियान संचालित करने आदि दायित्वों का निर्वहन करेगी।
- टास्क फोर्स की शक्तियाँ और कार्यकाल :
  - ज़िला स्तर पर गठित टास्क फोर्स अनुसंधान, विश्लेषण, इम्पेक्ट असेसमेंट, फील्ड सर्वे, अध्ययन आदि कार्यों के लिये विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों के विशेषज्ञों की सेवाओं के उपयोग के लिये समन्वय स्थापित करेगी।
  - साथ ही, सड़क सुरक्षा से संबंधित कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण के लिये सड़क सुरक्षा सलाहकार की सेवाएँ ले सकेंगी।
  - ज़िला सड़क सुरक्षा टास्क फोर्स का कार्यकाल 3 वर्ष के लिये होगा।

## राजस्थान साहित्य प्रोत्साहन पुरस्कार की होगी शुरुआत

### चर्चा में क्यों ?

14 जून, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के साहित्यकारों को राजस्थान साहित्य प्रोत्साहन पुरस्कार से सुशोभित करने के संबंध में प्रक्रिया, मार्गदर्शिका एवं चयन समिति से संबंधित प्रस्ताव का अनुमोदन किया है।

### प्रमुख बिंदु

- प्रोत्साहन में श्री कन्हैया लाल सेठिया, श्री कोमल कोठारी, डॉ. सीताराम लालस एवं श्री विजयदान देथा के नाम से पुरस्कार दिए जाएंगे।
- पद्य श्रेणी में श्री कन्हैया लाल सेठिया साहित्य पुरस्कार, लोक साहित्य/कला श्रेणी में श्री कोमल कोठारी लोक साहित्य पुरस्कार, भाषा/अनुसंधान श्रेणी में डॉ. सीताराम लालस भाषा एवं अनुसंधान पुरस्कार तथा गद्य श्रेणी में श्री विजयदान देथा साहित्य पुरस्कार दिए जाएंगे।

नोट :

- राजस्थान साहित्य अकादमी, उदयपुर को इन पुरस्कारों के लिये नोडल एजेंसी बनाया गया है। कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्त्व विभाग प्रशासनिक विभाग होगा।
- पुरस्कार में 11-11 लाख रुपए नकद राशि, प्रशस्ति–पत्र एवं शॉल प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा। ये पुरस्कार मरणोपरांत भी प्रदान किये जा सकेंगे।
- ये सम्मान उन व्यक्तियों, संस्था अथवा संगठन में बांटा जा सकेगा, जिन्हें चयन समिति समान रूप से पात्र समझती है। सभी पुरस्कार राज्य सरकार द्वारा आयोजित राजस्थान लिटरेचर फेस्टिवल, राजस्थान दिवस अथवा अन्य अवसरों पर प्रदान किए जा सकेंगे।
- पुरस्कार चयन के लिये गठित स्थायी समिति के अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा मनोनीत गैर-राजकीय व्यक्ति होंगे।
- पद्मश्री/साहित्य अकादमी सम्मान से सम्मानित राज्य सरकार द्वारा मनोनीत दो साहित्यकार, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के अध्यक्ष, राजस्थानी भाषा, साहित्य एवं संस्कृति अकादमी, बीकानेर के अध्यक्ष एवं कला एवं संस्कृति विभाग के प्रमुख शासन सचिव इस समिति में सदस्य तथा उप शासन सचिव सदस्य सचिव होंगे।
- समिति प्राप्त आवेदनों के विचारण के बाद तीन-तीन के समूह में चयनित साहित्यकारों का पैनल बनाकर अनुशंसा सहित अंतिम निर्णय के लिये प्रशासनिक विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री को प्रस्तुत करेगी।

## मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना-2023

### चर्चा में क्यों ?

14 जून, 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के असंगठित क्षेत्र के निर्माण श्रमिक कल्याण कोष के तहत पंजीकृत सक्रिय श्रमिकों एवं चिन्हित स्ट्रीट वैंडर्स को अस्पताल में भर्ती होने के दौरान राहत पहुँचाने हेतु 'मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना-2023' के प्रारूप को सहमति प्रदान की है।

### प्रमुख बिंदु

- 'मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना-2023' के तहत अब पंजीकृत श्रमिक व चिन्हित स्ट्रीट वैंडर्स और उनके परिवार के 25 से 60 वर्ष के सदस्य (पंजीकृत सक्रिय श्रमिक) को अस्पताल में भर्ती के दौरान अधिकतम 7 दिन की आर्थिक सहायता मिलेगी।
- योजना के तहत भर्ती के समय दैनिक मज़दूरी समाप्त होने की स्थिति में श्रमिक के खाते में ऑटो डीबीटी से भर्ती की अवधि या 7 दिवस (जो भी कम हो) के लिये प्रतिदिन 200 रुपए की सहायता पहुँचाई जाएगी। यह सहायता लाभार्थी के स्वयं या परिवार के सदस्य के अस्पताल में न्यूनतम 24 घंटे भर्ती होने की स्थिति में मिलेगी।
- श्रमिक की अस्पताल में मृत्यु होने की स्थिति में भी योजना के तहत सहायता प्राप्त की जा सकेगी।

## प्रदेश में लोक कला विकास बोर्ड का होगा गठन

### चर्चा में क्यों ?

14 जून, 2023 को राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की लोक कला से जुड़ी विभिन्न जातियों एवं वर्गों के उत्थान के लिये लोक कला विकास बोर्ड का गठन किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी।

### प्रमुख बिंदु

- इस बोर्ड में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के अलावा 7 गैर-सरकारी सदस्य होंगे। बोर्ड सचिव एवं कार्यकारी स्टाफ अलग से होगा। बोर्ड के गठन की कार्यवाही के लिये नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी।
- बोर्ड गठन का उद्देश्य लोक कला एवं कलाकारों को वैश्विक पहचान दिलवाना, रोजगार से जोड़ना, लोक कला संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना, कलाकारों को मंच उपलब्ध कराना, कलाओं का प्रचार-प्रसार, संस्थाओं का पर्यवेक्षण करना शामिल है।
- इनके अलावा बोर्ड द्वारा सांस्कृतिक आदान-प्रदान सुनिश्चित करना, लोक कलाओं के संबंध में प्रकाशन, समीक्षा करना, लोक कला मेलों, प्रदर्शनी, व्याख्यानमाला, गोष्ठियों, समारोह का आयोजन करना तथा लोक कलाकारों का संरक्षण एवं संवर्द्धन करना है।

नोट :

## पवन ऊर्जा के क्षेत्र में केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान प्रथम पुरस्कार से सम्मानित

### चर्चा में क्यों ?

15 जून, 2023 को केंद्र सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा राजस्थान को पवन ऊर्जा के क्षेत्र में अन्य राज्यों की अपेक्षा सर्वोत्कृष्ट कार्य किये जाने हेतु प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

### प्रमुख बिंदु

- 'ग्लोबल विंड डे'(15 जून) के अवसर पर नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तत्वावधान में नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में यह पुरस्कार प्रदान किया गया।
- राज्य सरकार की ओर से प्रमुख शासन सचिव, ऊर्जा भास्कर ए.सावंत ने केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव बी. एस.भल्ला से यह सम्मान प्राप्त किया।
- राज्य के ऊर्जा मंत्री भँवर सिंह भाटी ने कहा कि राजस्थान सरकार द्वारा जारी निवेशोन्मुखी अक्षय ऊर्जा नीतियों के कारण राजस्थान सौर ऊर्जा में तो अव्वल है ही, साथ ही वर्ष 2022-23 में देश में सर्वाधिक पवन ऊर्जा परियोजनाएँ स्थापित कर पवन ऊर्जा के क्षेत्र में भी देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।
- इस अवसर पर प्रमुख शासन सचिव भास्कर ए.सावंत ने अवगत कराया कि वर्ष 2022-23 में प्रदेश में 867 मेगावाट क्षमता की नई पवन ऊर्जा परियोजनाएँ स्थापित की गई जो कि अन्य राज्यों की अपेक्षा सर्वाधिक है।
- वर्ष 2022 में प्रदेश में 4337 मेगावाट पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित की गई थी जो कि मार्च 2023 तक बढ़कर 5204 मेगावाट हो गई।

## वन्य जीवों के संरक्षण हेतु 9 करोड़ रुपए स्वीकृत

### चर्चा में क्यों ?

18 जून, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के तीन स्थानों पर वन्य जीव संरक्षण के लिये विकास कार्यों हेतु 9 करोड़ रुपए स्वीकृत किये हैं।

नोट :

### प्रमुख बिंदु

- उक्त राशि से राज्य के पालीघाट सवाई माधोपुर (राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य) में घड़ियालों के संरक्षण के लिये 2 करोड़ रुपए, खींचन जोधपुर में कुरजां संरक्षण के लिये 2 करोड़ रुपए एवं राष्ट्रीय मरु उद्यान में गोडावन संरक्षण के लिये 5 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाए जाएंगे।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने इस संबंध में राज्य बजट 2023-24 में घोषणा की थी।

## राजस्थान किसान महोत्सव

### चर्चा में क्यों ?

18 जून, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में चल रहे तीनदिवसीय राजस्थान किसान महोत्सव का समापन किया।

### प्रमुख बिंदु

- राजस्थान किसान महोत्सव जैसे आयोजनों से किसानों को खेती की नई तकनीकों और कृषि उपकरणों के बारे में जानकारी मिलेगी तथा उनके उत्पादों का व्यापक प्रचार-प्रसार होगा।
- इस अवसर पर 'आत्मा योजना'के तहत कृषि एवं पशुपालन के क्षेत्र में नवाचार करने वाले प्रगतिशील 10 किसानों एवं पशुपालकों को राज्यस्तरीय कृषक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रत्येक किसान को 50 हज़ार रुपए की राशि पुरस्कार स्वरूप दी गई।
- इनमें जयपुर ज़िले से रूकमा देवी, टोंक से भूरी देवी मीणा, बाड़मेर से धर्माराम, डूँगरपुर से नारायण, भीलवाड़ा से कमला देवी, श्रीगंगानगर से पुनीत चौधरी, जैसलमेर से खुशालाराम, राजसमंद से बालूसिंह, धौलपुर से नीरज कुमार त्यागी तथा टोंक से भरतराम शामिल रहे।
- इस दौरान 'कृषक कल्याण को समर्पित 4 वर्ष'विषय तथा राजस्थान किसान ऐप पर आधारित लघु फिल्मों का प्रदर्शन किया गया।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने खेती और किसान को प्राथमिकता देते हुए नीतियाँ और कार्यक्रम बनाए हैं। कृषकों और पशुपालकों को समृद्ध और खुशहाल बनाने के उद्देश्य की पूर्ति के लिये 12 कृषि मिशन शुरू किये गए हैं और प्रत्येक बिंदु पर योजना बनाकर कार्य किया जा रहा है।
- उन्होंने कहा कि राज्य के 21 लाख किसानों का 15 हज़ार करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया गया। किसानों के लिये देश में पहली बार पृथक् कृषि बजट पेश किया गया। कृषि का बजट 2018-19 की तुलना में लगभग दोगुना कर दिया गया है।
- राज्य सरकार द्वारा किसानों को 90 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली उपलब्ध करवाने तथा 2000 यूनिट तक नि:शुल्क बिजली देने से उन्हें बड़ी राहत मिली है। एग्रो एवं फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा 2 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी दी जा रही है।
- राज्य के युवा उद्यमियों के लिये एमएसएमई एक्ट लाया गया है। इसमें उद्योग लगाने के लिये सरकार द्वारा दी जाने वाली ज़रूरी अनुमतियों में 5 वर्ष की छूट दी गई है।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने लम्पी रोग से पीड़ित 40 हज़ार से अधिक पशुपालकों को 175 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी। ऐसा फैसला करने वाला राजस्थान देश का इकलौता राज्य है।
- उन्होंने कहा कि दो दुधारू पशुओं का 40-40 हज़ार रुपए का बीमा किया जा रहा है। दुग्ध उत्पादकों को दूध पर 5 रुपए प्रति लीटर अनुदान दिया जा रहा है। अब राजस्थान दुग्ध उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर आ गया है।

नोट :

राजस्थान किसान महोत्सव
में आपका हार्दिक स्वागत है
मुख्यमंत्री
कामधेनु
पशु बीमा योजना
40 हजार रु

भारतीय स्टेट बैंक
State Bank Of India
राज्य स्तरीय कृषक पुरस्कार
2022-23
PAY Dharmaram
RUPEES Fifty Thousand Only
₹ 50,000/-

नोट :

## विभिन्न ज़िलों के 441 गाँवों में खुलेंगे नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र

### चर्चा में क्यों ?

17 जून, 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार तथा आमजन को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने की दिशा में प्रदेश के विभिन्न ज़िलों के 441 गाँवों में नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने तथा प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र हेतु महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता का एक-एक पद सृजित करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी प्रदान की है।

### प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री की इस मंज़ूरी से प्रदेश की गाँव-ढाणी में चिकित्सा सेवाओं का विस्तार होगा तथा स्थानीय लोगों को क्षेत्र में ही बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।
- प्रस्ताव के अनुसार बाड़मेर के 39, दौसा के 33, जयपुर-प्रथम के 25, सीकर के 25, अलवर के 23, जैसलमेर के 22, नागौर के 20, झुन्झूनूं के 20, भरतपुर के 19, अजमेर के 17, डूँगरपुर के 15, हनुमानगढ़ के 15, करौली के 14, चूरू के 14, जयपुर-द्वितीय के 14, बारां के 14, भीलवाड़ा के 12, जोधपुर के 12 नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे।
- इनके अलावा टोंक के 12, राजसमंद के 10, कोटा के 9, बीकानेर के 9, धौलपुर के 6, बूंदी के 6, उदयपुर के 6, बांसवाड़ा के 5, चितौड़गढ़ के 5, सवाई माधोपुर के 5, गंगानगर के 5, सिरोही के 4, जालोर के 4 एवं पाली के 2 सहित कुल 441 गाँवों में नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे।
- उप स्वास्थ्य केंद्रों का संचालन भवन निर्माण होने तक उपलब्ध राजकीय भवन अथवा किराये के भवन में किया जाएगा। साथ ही, प्रत्येक उप स्वास्थ्य केंद्र हेतु महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता का 1-1 पद (कुल 441 पद) सृजित किया जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट 2023-24 में प्रदेश में नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने की घोषणा की गई थी।

नोट :

# एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड ने आईआईटी जोधपुर में अपनी पहली रूफटॉप सौर विद्युत परियोजना शुरू की

## चर्चा में क्यों ?

16 जून, 2023 को पत्र सूचना कार्यालय भारत सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड (एनवीवीएन) ने 14 जून, 2023 को आईआईटी जोधपुर (राजस्थान) में अपनी पहली रूफटॉप सौर फोटोवोल्टिक परियोजना शुरू की है।

## प्रमुख बिंदु

- एक मेगावाट ग्रिड से जुड़ी यह सौर परियोजना 25 साल के विद्युत खरीद समझौते की अवधि के लिये नवीकरणीय ऊर्जा सेवा कंपनी (आरईएससीओ) मॉडल के तहत एनवीवीएन द्वारा लागू की गई है।
- आरईएससीओ मॉडल के तहत रूफटॉप सौर संस्थापन की स्थापना के लिये एक नवीकरणीय ऊर्जा सेवा कंपनी (रेस्को) संपूर्ण सौर ऊर्जा संयंत्र (रूफ या ग्राउंड-माउंटेड) का डिज़ाइन, निर्माण, धन और संचालन करती है और उपभोक्ता प्रति किलोवाट विद्युत उत्पादन से सुनिश्चित मासिक यूनिटों के लिये विकासकर्त्ता को भुगतान करता है तथा डिस्कॉम उत्पादित विद्युत इकाइयों को उपभोगता के विद्युत बिल में समायोजित करता है।
- यह परियोजना आईआईटी जोधपुर के परिसर में 14 भवनों की छतों पर स्थापित की गई है। इस परियोजना से प्रति वर्ष लगभग 14.9 लाख यूनिट विद्युत का उत्पादन होगा और इससे आईआईटी जोधपुर की 15 प्रतिशत बिजली की आवश्यकता पूरी होगी।
- इस परियोजना के परिणामस्वरूप कार्बन डाईऑक्साइड के उत्सर्जन में प्रति वर्ष 1,060 टन की कमी आएगी।
- उल्लेखनीय है कि एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड का गठन वर्ष 2002 में देश में विद्युत व्यापार की क्षमता का उपयोग करने के लिये एनटीपीसी द्वारा किया गया था। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के नवीनतम विनियमन के अनुसार एनवीवीएन के पास उच्चतम श्रेणी 'आई'का विद्युत व्यापार लाइसेंस है।
- एनवीवीएन जिप्सम का व्यापार कर रही है और यह अब नवीनीकरण, ई-गतिशीलता, अपशिष्ट को हरित ईंधन में परिवर्तित करने के क्षेत्रों में अपना कार्य विस्तार कर रही है तथा विद्युत मूल्य श्रृंखला में समस्त व्यापार समाधान उपलब्ध करा रही है।

नोट :

## जोधपुर में खुलेगा हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय

### चर्चा में क्यों ?

19 जून, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के शिल्पकारों तथा बुनकरों के उत्थान के लिये जोधपुर में हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय खोले जाने से संबंधित प्रस्ताव को मंज़ूरी दी है।

### प्रमुख बिंदु

- प्रस्ताव के अनुसार, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त इस हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय के पदेन निदेशक होंगे। निदेशालय हेतु अतिरिक्त निदेशक उद्योग एवं वाणिज्य का एक नवीन पद सृजित किया जाएगा।
- निदेशालय के मार्केटिंग, ई-कॉमर्स एवं डिजाइन एक्सपर्ट के कार्यों के लिये विशेषज्ञों की सेवाएँ ली जा सकेंगी। निदेशालय हेतु अन्य अधिकारी-कर्मचारी उद्योग एवं वाणिज्य विभाग से पदस्थापित किये जाएंगे।
- हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय का मुख्य कार्य राज्य के हस्तशिल्प एवं हथकरघा क्षेत्र का विकास करना होगा।
- यह निदेशालय राज्य के शिल्पियों एवं बुनकरों के उत्थान के लिये कार्य करेगा, जिसके परिणामस्वरूप राज्य में रोज़गार के नए अवसर सृजित होने के साथ-साथ निर्यात में भी वृद्धि होगी। साथ ही, निदेशालय हस्तशिल्प नीति-2022 के अनुसार विभिन्न कार्यों को संपादित करेगा।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने 21 मार्च, 2023 को राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो के उद्घाटन समारोह में इस निदेशालय को जोधपुर में खोले जाने की घोषणा की थी।

## धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये 13.48 करोड़ रुपए स्वीकृत

### चर्चा में क्यों ?

19 जून, 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के नागौर, जैसलमेर तथा अलवर के धार्मिक स्थलों पर धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये 13.48 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव का अनुमोदन किया है।

### प्रमुख बिंदु

- विदित है कि राज्य सरकार धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने तथा ऐसे स्थानों पर यात्रियों के लिये विभिन्न सुविधाएँ विकसित करने के लिये निरंतर कार्य कर रही है। इसी क्रम में नागौर ज़िले में बुटाटी, घाटवेश्वर महादेव मंदिर, हरमल दास जी महाराज मंदिर तथा दरगाह हजरत सम्मन बड़ी खाटू में कुल 7.74 करोड़ रुपए के विभिन्न पर्यटन विकास कार्य कराए जाएंगे।
- मुख्यमंत्री ने जैसलमेर स्थित ऐतिहासिक धार्मिक पर्यटन स्थल श्री काले डूंगर राय मंदिर परिसर में विकास कार्यों के लिये 1.50 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है।
- इस राशि से मंदिर प्रांगण में मार्बल टाइल्स, सोलर पावर प्लांट, नवीन धर्मशाला निर्माण, मंदिर परिसर में लगी बेंचों की मरम्मत, मंदिर तक जाने के लिये सीसी रोड, जैसलमेर-जेठवाई-काले डूंगर सड़क के उन्नयन सहित विभिन्न विकास कार्य होंगे।
- मुख्यमंत्री ने अलवर ज़िले के बानसूर किला स्थित माताजी मंदिर तथा गंगा माता मंदिर, तालवृक्ष में विकास कार्य करवाने के लिये 4.24 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव का अनुमोदन किया है।
- स्वीकृत राशि से बानसूर किला स्थित माताजी मंदिर में सीढ़ियों की मरम्मत, किले में नए पाथ-वे का निर्माण, स्टील रेलिंग, नवीन हॉल, पत्थर की बेंचों का निर्माण, सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना तथा मंदिर प्रांगण में विभिन्न उन्नयन कार्य कराए जाएंगे।
- साथ ही, गंगा माता मंदिर, तालवृक्ष में नवीन धर्मशाला निर्माण, सोलर लाइट, मंदिर परिसर में पार्किंग, चारदीवारी निर्माण सहित विभिन्न कार्य किये जाएंगे।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने वर्ष 2023-24 के बजट में इस संबंध में घोषणा की थी।

नोट :

## कॉलेज में अध्ययनरत छात्राओं के लिये भी 'ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम' लागू

### चर्चा में क्यों ?

20 जून, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्राओं को राहत देने के लिये 'ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम' के प्रस्ताव को मंज़ूरी प्रदान की है।

### प्रमुख बिंदु

- 'ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम' के तहत कॉलेज में अध्ययनरत छात्राओं को भी अब घर से कॉलेज आने-जाने का बस किराया मिलेगा।
- राज्य सरकार द्वारा कॉलेज में 10 किमी. से अधिक दूरी से आवागमन पर प्रति दिवस 20 रुपए का भुगतान किया जाएगा। यह राशि छात्राओं द्वारा आवेदन पत्र में दिये गए बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी।
- माह में न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति वाली छात्राएँ ही स्कीम में पात्र होंगी। इसके लिये कॉलेज में आधार आधारित बायोमैट्रिक मशीन पर उपस्थिति होगी।
- उल्लेखनीय है कि वर्तमान में कक्षा 9 से 12 तक अध्ययनरत छात्राओं के लिये घर से 5 किमी. से अधिक दूरी से विद्यालय में आवागमन पर यह लाभ देय है।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने वर्ष 2023-24 के बजट में उच्च शिक्षण संस्थानों में ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना लागू करने की घोषणा की थी।

## प्रदेश में शोधार्थियों को मिलेगा आर्थिक संबल एवं प्रोत्साहन

### चर्चा में क्यों ?

20 जून, 2023 को प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के राजकीय महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के लगभग 6 हज़ार शोधार्थियों को आर्थिक संबल एवं प्रोत्साहन प्रदान करने के लिये फैलोशिप देने हेतु 62.30 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव का अनुमोदन किया है।

### प्रमुख बिंदु

- राजकीय महाविद्यालयों एवं राज्य सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों के लगभग 2200 शोधार्थियों को 20 हज़ार रुपए प्रतिमाह की फैलोशिप दी जाएगी। इसके लिये 52.80 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है।
- साथ ही राजकीय महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत 3800 शोधार्थियों को देश के प्रतिष्ठित उच्च शिक्षण संस्थानों एवं शोध संस्थानों में इंटर्नशिप, सेमिनार, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस में सहभागिता के लिये 25 हज़ार रुपए तक की वित्तीय सहायता मिलेगी। इसके लिये 9.50 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है।
- यह फैलोशिप अधिकतम 2 वर्ष के लिये दी जाएगी। कॉलेज शिक्षा विभाग इसका नोडल विभाग होगा।
- राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में इन शोधार्थियों का सहयोग लिया जा सकेगा।
- इनमें चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालयों के शोधार्थी तथा अन्य किसी भी तरह की फैलोशिप प्राप्त करने वाले शोधार्थी पात्र नहीं होंगे।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने वर्ष 2023-24 के बजट में इस संबंध में घोषणा की थी।

## गोडवाड़ देसुरी में लेपर्ड कन्जर्वेशन रिजर्व होगा विकसित

### चर्चा में क्यों ?

21 जून, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में वन क्षेत्र विकास एवं पर्यावरण संरक्षण करने हेतु राज्य के पाली ज़िले के गोडवाड़ देसुरी में लेपर्ड कन्जर्वेशन रिजर्व विकसित करने तथा सिरोही के संरक्षित वन क्षेत्र वाडाखेड़ा में विभिन्न विकास कार्यों के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

नोट :

### प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने इन कार्यों के लिये लगभग 5.15 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी है तथा गोडवाड़ देसुरी में 2 करोड़ रुपए की लागत से लेपर्ड कन्जर्वेशन रिजर्व विकसित किये जाने के कार्य होंगे।
- साथ ही संरक्षित वन क्षेत्र वाडाखेड़ा में 3.15 करोड़ रुपए की लागत से विकास एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य कराए जाएंगे।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा बजट वर्ष 2023-24 में इन कार्यों के लिये घोषणा की गई थी।

## चिकित्सा मंत्री ने किया पीसीटीएस मोबाइल एप लॉन्च

### चर्चा में क्यों ?

21 जून, 2023 को राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने राज्य में गर्भवती महिलाओं, प्रसूताओं एवं शिशुओं को प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सेवाओं की ऑनलाईन ट्रैकिंग, रिपोर्टिंग और मॉनिटरिंग के लिये पीसीटीएस मोबाइल एप लॉन्च किया साथ ही इससे संबंधित पोस्टर का विमोचन भी किया।

### प्रमुख बिंदु

- पीसीटीएस मोबाइल एप के माध्यम से प्रदेश की 53 हज़ार से ज्यादा आशाएँ मोबाइल पर उनके क्षेत्र की महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित स्वास्थ्य सेवाओं की डे-टू-डे रिपोर्टिंग कर सकेंगी और इस कार्य की प्रभावी मॉनिटरिंग भी की जा सकेगी।
- चिकित्सा मंत्री ने कहा कि इस एप के माध्यम से राज्य की आशा सहयोगिनी बच्चों एवं महिलाओं को दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं से पूरी तरह अपडेट रहेगी। उन्हें पता रहेगा कि किस दिन किन बच्चों और महिलाओं का टीकाकरण होना है या किसी अन्य सेवा का लाभ दिया जाना है।
- इससे महिलाओं और बच्चों से संबंधित स्वास्थ्य सेवाओं को और मज़बूत किया जा सकेगा और इसके परिणामस्वरूप स्वास्थ्य सूचकांकों में और सुधार होगा।
- इस एप के माध्यम से प्रदेश की किसी भी आशा और एएनएम से विभाग के अधिकारी सीधी बात कर प्रगति रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। महिलाओं एवं बच्चों के टीकाकरण सहित अन्य सेवाओं की ऑनलाईन एंट्री आदि कार्य इसके माध्यम से किये जा सकेंगे।
- मिशन निदेशक एनएचम डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी ने बताया कि यह एप प्रदेश की आशा सहयोगिनियों के कार्य को सुगम और प्रभावी बनाने के लिये विभाग की एक अभिनव पहल है, जिसे एनआईसी राजस्थान और डेमोग्राफर अनुभाग के माध्यम से तैयार करवाया गया है।
- उन्होंने बताया कि उप स्वास्थ्य केंद्रों पर डेटा एंट्री की सुविधा के अभाव के कारण इससे पूर्व आशाओं को गर्भवती महिलाओं, प्रसूताओं एवं शिशुओं को प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं के डेटा को अपने क्षेत्र की पीएचसी/सीएचसी/अन्य चिकित्सा संस्थान पर जाकर अपडेट करवाना पड़ता था, जिससे समय पर ऑनलाईन सूचना भेजने में अनावश्यक विलंब होता था। इस एप के माध्यम से रियल टाईम सूचना प्राप्त हो सकेगी।
- इस एप पर आशा द्वारा मासिक कार्य योजना, एएनसी, पीएनसी/एचबीएनसी, टीकाकरण, नसबंदी, अंतराल साधन की सर्विसेज की नामवार सूची, गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जाँच, प्रसव पश्चात् देखभाल, शिशु टीकाकरण, बच्चों का ग्रोथ चार्ट, शिशु एवं मातृ मृत्यु दर की जानकारी संबंधी सेवाएँ उपलब्ध होगी।
- इनके अलावा बच्चों को 3, 6, 9, 12 व 15 माह पर दी जाने वाली एचबीवाईसी सेवाएँ, महिला की पीसीटीएस आईडी को सर्च करने की सुविधा, सुझावपरक वीडियो, आशा को आशा सॉफ्ट के माध्यम से भुगतान की गई प्रोत्साहन राशि का विवरण तथा रेफर करने हेतु नजदीकी संस्थाओं की जिओ मैपिंग के माध्यम से जानकारी की सेवाएँ उपलब्ध होगी।
- एप के क्रियान्वयन एवं कवरेज में प्रदेश के 14 हज़ार 843 उप स्वास्थ्य केंद्र, 214 जनता क्लिनिक, 2 हज़ार 655 पीएचसी, 769 सीएचसी, 46 ज़िला अस्पताल, 67 उप ज़िला अस्पताल, 13 सैटेलाईट अस्पताल, 141 मेडिकल कॉलेज/सिटी डिस्पेंसरी तथा 47 अन्य चिकित्सा संस्थान शामिल हैं।
- गौरतलब है कि पूर्व में विभाग द्वारा नवाचार के तहत वर्ष 2008 में पीसीटीएस सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया था। इस दौरान यह देखा गया कि वर्ष 2008 में प्रदेश की शिशु मृत्यु दर प्रति हज़ार जीवित जन्म पर 63 थी, जो स्वास्थ्य सेवाओं के प्रभावी क्रियान्वयन व पीसीटीएस सॉफ्टवेयर की मदद से वर्ष 2020 में घटकर 32 प्रति हज़ार जीवित जन्म रह गई। इसी प्रकार मातृ मृत्यु दर भी 318 से घटकर 113 रह गई।

नोट :

## राजस्थान राज्य स्वर्ण रजत कला विकास बोर्ड का होगा गठन

### चर्चा में क्यों ?

21 जून, 2023 को प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान राज्य स्वर्ण रजत कला विकास बोर्ड के गठन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इसका मुख्यालय जयपुर में होगा।

### प्रमुख बिंदु

- बोर्ड में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा 5 गैर-सरकारी सदस्य होंगे। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का रहेगा।
- साथ ही उद्योग विभाग, स्कूल शिक्षा (प्राथमिक/माध्यमिक) एवं संस्कृत शिक्षा विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, श्रम विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासनए सचिव/शासनए सचिव अथवा उनके प्रतिनिधि बोर्ड में सरकारी सदस्य के रूप में होंगे।
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी सचिव का कार्य करेंगे।
- बोर्ड में राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक या उनके प्रतिनिधि विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे।
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग बोर्ड का प्रशासनिक विभाग होगा।

## आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा को मिला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड

### चर्चा में क्यों ?

22 जून, 2023 को 'द एशिया एचआरडी कॉन्ग्रेस'ने राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के आयुक्त पवन अरोड़ा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवॉर्ड के साथ मंडल द्वारा निर्मित कोचिंग हब, एआईएस रेजिडेंसी, जयपुर चौपाटी और मुख्यमंत्री जन आवास योजना के लिये 4 पुरस्कारों से सम्मानित किया।

नोट :

## प्रमुख बिंदु

- जयपुर के एक 5 सितारा होटल में आयोजित भव्य समारोह में पवन अरोड़ा को व्यक्तिगत पुरस्कारों की श्रेणी में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया।
- 'द एशिया एचआरडी कॉन्ग्रेस' ने कोचिंग हब को इन्नोवेटिव प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर, एआईएस रेजिडेंसी को बेस्ट इनोवेशन इन प्रोडक्ट डिजाइन, मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत बन रहे फ्लैट्स को डेवलपर ऑफ द ईयर (एफोर्डिंग हाउसिंग) और जयपुर चौपाटी को डेवलपर ऑफ द ईयर (रिटेल) की श्रेणी में सम्मानित किया गया है।
- गौरतलब है कि समारोह में सराहे गए कोचिंग हब, जयपुर चौपाटी, एआईएस रेजीडेंसी और मुख्यमंत्री जन आवास योजना इससे पूर्व भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खासी चर्चित रह चुके हैं।
- प्रताप नगर और मानसरोवर में स्थापित चौपाटी के लजीज क्यूजीन और व्यंजनों के तो शहरवासी दीवाने हैं। चौपाटियों के शुरुआती 5 महीनों में अधिकतम फुटफाल के लिये तो दो अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड भी मिल चुके हैं। चौपाटियों पर चलने वाला लाइव बैंड के आगंतुक खासे मुरीद हैं।
- प्रताप नगर में बना कोचिंग हब देश का पहला ऐसा संस्थान है, जहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त भवन में निजी कोचिंग संस्थान एक साथ संचालित होने को हैं।
- मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत बने आवास भी गुणवत्ता और सुविधाओं के मामले में हर स्तर पर खरे उतरते हैं। इसके अलावा ऑल इंडिया सर्विस (एआईएस) रेजिडेंसी देश की एकमात्र अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त रेजिडेंसी है, जिसे कई बार राष्ट्रीय स्तर पर सराहा जा चुका है।
- उल्लेखनीय है कि आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा की अगुवाई में पिछले चार वर्षों में मंडल को कुल 27 अवार्ड मिल चुके हैं। इनमें मकान विक्रय में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, स्कॉच अवार्ड-2021, अवार्ड ऑफ एक्सीलेंसी, नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा सम्मान, नेशनल हाउसिंग अवार्ड, आई.बी.सी और 'स्टार ऑफ गवर्नेंस-गोल्ड अवार्ड' और नरेडको द्वारा दिये 'रियल एस्टेट कॉन्क्लेव', 'ओएमजी-बुक ऑफ रिकार्डस'जैसे प्रतिष्ठित अवार्ड शामिल हैं।

नोट :

## नीरज तंबोलिया 'राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड -2022' से सम्मानित

### चर्चा में क्यों ?

22 जून, 2023 को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु, जो सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर हैं, ने नई दिल्ली में आयोजित समारोह में जयपुर स्थित जे.के. लोन अस्पताल में कार्यरत सीनियर नर्सिंग ऑफिसर नीरज तंबोलिया को नर्सिंग क्षेत्र में उनके समर्पण और उत्कृष्ट सेवाभाव के लिये 'राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड-2022' से सम्मानित किया।

### प्रमुख बिंदु

- राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने समारोह में वर्ष 2022 एवं 2023 के लिये कुल 30 नर्सों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किया है।
- जे.के. लोन अस्पताल में कार्यरत सीनियर नर्सिंग ऑफिसर नीरज तंबोलिया ने अपने 31 वर्ष के सेवाकाल के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतरीन काम किया है। उन्हें रोड एक्सीडेंट में घायल लोगों को बचाने, आईसीयू में शार्ट सर्किट से लगी आग से रोगियों को निकालने में तथा कोरोना के दौरान रोगियों को निस्वार्थ सेवाभाव और साहस के साथ बचाने के साथ-साथ स्वास्थ्य शिक्षा के कार्यों में अनवरत सहयोग देने के लिये राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2022 दिया गया है।
- विदित है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 1973 में संस्थापित राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार नर्सों और नर्सिंग प्रोफेशनलों को समाज को प्रदान की गई उनकी सराहनीय सेवाओं के सम्मानस्वरूप दिया जाता है।

## सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने पालनहार फेस रिकॉग्निशन नवीनीकरण मोबाइल एप किया लॉन्च

### चर्चा में क्यों ?

22 जून, 2023 को राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने अंबेडकर भवन स्थित निदेशालय के सभागार में पालनहार योजना के तहत पालनहार फेस रिकॉग्निशन नवीनीकरण मोबाइल एप लॉन्च किया।

नोट :

## प्रमुख बिंदु

- उन्होंने बताया कि पालनहार द्वारा स्वयं का सत्यापन एवं बच्चों के शैक्षणिक नवीनीकरण की सुविधा मोबाइल के माध्यम से स्वयं के स्तर (डोर स्टेप सर्विस डिलीवरी) पर उपलब्ध हो सकेगी, जिससे समय की भी बचत होगी।
- विदित है कि पालनहार योजना राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना है। राज्य सरकार द्वारा 7 लाख से अधिक लाभार्थियों को योजना का लाभ दिया जा रहा है।
- योजना के तहत वार्षिक सत्यापन/नवीनीकरण की प्रक्रिया को सुलभ, सरल एवं त्वरित बनाये जाने हेतु वर्तमान में उपलब्ध सत्यापन/नवीनीकरण की विधियों के अतिरिक्त तकनीक का उपयोग कर पालनहार मोबाइल एप विकसित किया गया है।
- पालनहार मोबाइल एप के माध्यम से वार्षिक भौतिक सत्यापन/नवीनीकरण करने हेतु एंड्रायड मोबाइल, एंड्राइड टेबलेट, मोबाइल पर पालनहार मोबाइल एप व फेस आरडी एप को इंस्टाल करना होगा।
- पालनहार मोबाइल ऐप प्रारंभ करने पर सबसे पहले मोबाइल का नंबर दर्ज कर ओ.टी.पी प्राप्त करना होगा। प्राप्त ओ.टी.पी. दर्ज करने के बाद पालनहार के भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी, जिसके एक सेशन के दौरान एक से अधिक पालनहार का भी सत्यापन किया जा सकेगा।
- पालनहार मोबाइल एप पर फेस रिकॉग्निशन के माध्यम से पालनहार का आधार पोर्टल पर उपलब्ध डेटा के द्वारा वार्षिक सत्यापन एवं बच्चों का आंगनवाड़ी केंद्र में पंजीकृत होने/विद्यालय में अध्ययनरत रहने का वार्षिक शैक्षणिक नवीनीकरण किये जाने हेतु प्रावधान किया गया है।
- विभाग द्वारा वर्तमान में पालनहार योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष पालनहार/बच्चों का वार्षिक भौतिक सत्यापन/नवीनीकरण करवाया जाता है, जो कि एक नियमित प्रक्रिया है। वर्तमान में पालनहार पोर्टल को विभागीय एवं अन्य संबंधित विभागों द्वारा संचालित पोर्टल्स से लिंक कर ऑनलाइन वेबसर्विस (API) के माध्यम से पालनहारों व बच्चों का जनाधार तथा आधार नंबर मैच करवाकर वार्षिक भौतिक सत्यापन/नवीनीकरण करवाया जा रहा है।

नोट :

## महिलाओं को अब रोडवेज की सभी श्रेणी की बसों में मिलेगी किराये में 50 प्रतिशत छूट

### चर्चा में क्यों ?

22 जून, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य की सीमा में अब राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की समस्त श्रेणी की बसों में यात्रा करने पर महिलाओं एवं बालिकाओं को 50 प्रतिशत की रियायत दिये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है।

### प्रमुख बिंदु

- प्रस्ताव के अनुसार, निगम की सभी श्रेणी की बसों में यात्रा करने पर महिलाओं एवं बालिकाओं का आधा किराया ही लगेगा। अभी केवल साधारण श्रेणी की बसों में यात्रा करने पर ही महिलाओं एवं बालिकाओं को 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही थी।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने बजट 2023-24 में रोडवेज की साधारण बसों में यात्रा करने पर महिलाओं को किराए में दी जा रही छूट को 30 से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की घोषणा की थी।
- यह घोषणा 1 अप्रैल, 2023 से क्रियान्वित भी की जा रही थी। तत्पश्चात् 25 मई, 2023 को जयपुर के सिंधी कैंप स्थित नवीन बस टर्मिनल के लोकार्पण समारोह में मुख्यमंत्री ने इस रियायत को रोडवेज की सभी श्रेणी की बसों में लागू करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने उक्त घोषणा की क्रियान्विति में यह स्वीकृति प्रदान की है।

## टाईगर रिजर्व रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य में जंगल सफारी का हुआ शुभारंभ

### चर्चा में क्यों ?

23 जून, 2023 को राजस्थान के युवा मामले, खेल तथा सूचना एवं जनसंपर्क राज्यमंत्री अशोक चांदना ने राज्य में पर्यटन के क्षेत्र में बूंदी ज़िले को आगे बढ़ाने के क्रम में बूंदी के दलेलपुरा स्थित वन नाके से टाईगर रिजर्व रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य में पहली जंगल सफारी को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया।

### प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर राज्यमंत्री ने कहा कि टाईगर सेंचुरी में सफारी का शुभारंभ पूरे ज़िले के लिये जीवनदान है। आने वाले समय में युवा पीढ़ी के लिये रोज़गार के दरवाज़े खुलेंगे।
- साथ ही विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। देश के कोने-कोने से आने वाले पर्यटक आनंदित होंगे और क्षेत्र के लोगों को रोज़गार मिलेगा।
- रामगढ़ विषधारी टाईगर रिजर्व में रवाना हुई जंगल सफारी में 4 विदेशी तथा 14 देशी सैलानियों को जिप्सी के माध्यम से जंगल की सैर कराई गई।
- टाईगर रिजर्व रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य की कई विशेषताएँ हैं। यह लगभग 1500 वर्ग किलोमीटर है इसमें 500 वर्ग किलोमीटर का कोर क्षेत्र है।
- इसमें विभिन्न प्रजातियों के जीव-जंतु निवास करते हैं। इन्हीं सब खूबियों से आने वाले दिनों में यह अभयारण्य पर्यटकों के लिये आकर्षण का प्रमुख केंद्र बनकर उभरेगा।
- जंगल सफारी के रूट पर टाईगर, पेंथर, चितली, हिरण, भालू, जंगली बिल्ली, चीतल, सांभर, लोमड़ी, नीलगाय, चीतल, बारहसिंगा, बंदर, लंगूर, नेवला, गिलहरी, सेही आदि का दीदार हो सकेगा।
- इसके अलावा मोर, बटेर, कबूतर, बगुला, चील, गिद्ध, उल्लू, गौरैया, तोता सहित एक सौ के करीब पक्षी नज़र आएंगे।
- जंगल सफारी का आनंद लेने के लिये देशी पर्यटकों को 780 रुपए प्रति पर्यटक तथा विदेशी पर्यटकों को प्रति पर्यटक 1150 रुपए की राशि तथा विद्यार्थियों को प्रति विद्यार्थी 700 रुपए खर्च करने होंगे।

नोट :

## 13 शहरों में विकसित होंगे 'ग्रीन लंग्स'

### चर्चा में क्यों ?

25 जून, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के 13 शहरों में 'ग्रीन लंग्स' विकसित करने के लिये 19 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति दी है।

### प्रमुख बिंदु

- उक्त राशि से 13 शहरों के आसपास वन क्षेत्रों का विकास किया जाएगा।
- स्वीकृति के अनुसार, अलवर के मूंगस्का, चूरू के राजगढ़, चित्तौड़गढ़ के मंगलवाड़, राजसमंद के नाथद्वारा व गणेश टेकड़ी एवं उदयपुर के रिसाला में 2-2 करोड़ रुपए तथा बारां के खैरखेड़ी, बांसवाड़ा के श्यामपुरा, चित्तौड़गढ़ के किला ब्लॉक, दौसा के नीलकंठ महादेव, जयपुर के कानोता बांध, राजसमंद के बांदरिया मगरा एवं टोंक के कच्चा बांध क्षेत्र में 1-1 करोड़ रुपए की लागत से वन क्षेत्रों का विकास कर आमजन के लिये खोला जाएगा।
- मुख्यमंत्री के इस निर्णय से इन शहरों में आमजन को शुद्ध वातावरण एवं हरियाली मिलेगी और पर्यावरण संरक्षण भी हो सकेगा।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट में इस संबंध में घोषणा की गई थी।

## राजस्थान को मिला जैम एक्सीलेंसी अवार्ड

### चर्चा में क्यों ?

26 जून, 2023 को नई दिल्ली के वाणिज्य भवन में आयोजित क्रेता विक्रेता गौरव सम्मान समारोह में राजस्थान को जैम एक्सीलेंसी अवार्ड दिया गया। प्रदेश को जैम पोर्टल के माध्यम से एससी-एसटी उपक्रमियों को उनके उत्पादों के क्रय आदेश दिलाने के बेहतर कार्य के लिये सिल्वर पुरस्कार प्रदान किया गया।

### प्रमुख बिंदु

- सम्मान समारोह में केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल एवं उद्योग राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल ने राजस्थान को सिल्वर पुरस्कार दिया। राजस्थान उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की ओर से अतिरिक्त निदेशक एस एस शाह ने यह पुरस्कार ग्रहण किया।

नोट :

- राजस्थान की उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत ने पुरस्कार मिलने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल पर सराहनीय कार्य के लिये यह पुरस्कार मिलना प्रदेश के लिये गौरव की बात है।
- विभाग के आयुक्त ओम कसेरा ने कहा कि प्रदेश में बेहतर औद्योगिक वातावरण विकसित करना विभाग की प्राथमिकता है एवं इस दिशा में विभाग निरंतर कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि नव उद्यमियों को प्रदेश में उद्योग नीति से सुगमता से उद्योग स्थापित करने एवं संचालित करने के लिये विभाग की ओर से हरसंभव मदद उपलब्ध करवाई जा रही है।

## मुख्य न्यायाधिपति ने 'आरएसएलएसए ( रालसा ) एट ए ग्लांस' पुस्तक का किया विमोचन

### चर्चा में क्यों ?

27 जून, 2023 को राजस्थान उच्च न्यायालय मुख्य पीठ (जोधपुर) में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति तथा आरएसएलएसए (रालसा) के मुख्य संरक्षक ऑगिस्टिन जार्ज मसीह की अध्यक्षता में रालसा की उपलब्धियाँ एवं गतिविधियों को समाहित करते हुए तैयार की गई पुस्तक 'आरएसएलएसए एट ए ग्लांस'का विमोचन किया गया।

### प्रमुख बिंदु

- इसके साथ ही दो जनकल्याणकारी स्कीम विशेष योग्यजनों के हितार्थ उनका पहचान पत्र सुनिश्चित करने एवं विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं यथा कृत्रिम अंग एवं अन्य लाभ उपलब्ध कराने के लिये योजना व आदर्श विधिक सेवा केंद्र योजना को लॉन्च किया गया।
- राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा रालसा के कार्यकारी अध्यक्ष, न्यायाधिपति मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव ने बताया कि 'आरएसएलएसए एट ए ग्लांस'पुस्तक का विमोचन, दिव्यांग व्यक्तियों को यू.डी.आई.डी. सर्टिफिकेट व अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिये योजना तथा प्रत्येक संभाग में दूरस्थ तालुका विधिक सेवा समिति में आदर्श विधिक सेवा केंद्र की योजना का शुभारंभ किया गया है।
- विशेष योग्यजन के चिह्नीकरण की दिशा में प्रारंभ की गई इस योजना से प्रत्येक विशेष योग्यजन को दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अर्थात् यू.डी.आई.डी. प्राप्त हो सकेगा और यू.डी.आई.डी. के अभाव में कोई व्यक्ति राज्य की कल्याणकारी योजनाओं या कृत्रिम अंग प्राप्त करने से वंचित नहीं रहेगा।

नोट :

- रालसा द्वारा चिह्नित की गई आदर्श तालुकाओं में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर आमजन को न केवल कानून के प्रति जागरूक किया जाएगा बल्कि उन्हें सरकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए उनका लाभ दिलाया जाना भी सुनिश्चित किया जाएगा।
- मुख्य न्यायाधिपति ऑगिस्टिन जार्ज मसीह ने बताया कि 'रालसा एट ए ग्लांस' पुस्तक रालसा की सराहनीय उपलब्धियों और वंचित वर्गों को कानूनी सहायता प्रदान करने के प्रति रालसा की अटूट प्रतिबद्धता की झलक पेश करती है।
- विशिष्ट योग्यजनों की पहचान करने और उन्हें यू.डी.आई.डी. प्रदान करने की यह योजना निश्चित रूप से एक प्रगतिशील कदम है। इससे विशिष्ट योग्यजनों को समाज की मुख्यधारा में शामिल हाने के साथ ही समान अधिकार व अवसर प्राप्त हो सकेंगे।
- रालसा के द्वारा शुरू किये गए आदर्श विधिक सेवा केंद्र को ज़रूरतमंद लोगों को उनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति की परवाह किये बगैर विधिक सहायता उपलब्ध कराएंगे जिससे वे कानूनी परिदृश्य से निपटने के लिये सशक्त हो सकेंगे।

## 36 न्याय क्षेत्रों में होगी वल्नरेबल विटनस डिपोजिशन सेंटर्स की स्थापना

### चर्चा में क्यों ?

27 जून, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के 36 न्याय क्षेत्रों के मुख्यालयों पर वल्नरेबल विटनस डिपोजिशन सेंटर्स की स्थापना की स्वीकृति दी है।

### प्रमुख बिंदु

- वल्नरेबल विटनस डिपोजिशन सेंटर्स की स्थापना से प्रदेश में बाल एवं यौन अपराधों के पीड़ितों एवं अन्य संवेदनशील गवाहों को सुरक्षित वातावरण में गवाही की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।
- मुख्यमंत्री ने सेंटर्स की स्थापना के लिये 9.56 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने बजट वर्ष 2023-24 में इस संबंध में घोषणा की थी।

नोट :

# 'डायल फ्यूचर'

## चर्चा में क्यों ?

27 जून, 2023 को राजस्थान के स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ ही भावी पीढ़ी के सुनहरे भविष्य की राह तैयार करने के लिये एक अनूठी पहल करते हुए 'डायल फ्यूचर'(भविष्य की राह) कार्यक्रम की शुरुआत की है।

## प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि डायल फ्यूचर और फ्यूचर स्टेप्स (भविष्य की राह) इनीशिएटिव के तहत राज्य के सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों से एक-एक शिक्षक का पथ प्रदर्शक के रूप में चयन किया गया है जो स्कूल में दसवीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाले बच्चों का संकाय चयन में मार्गदर्शन एवं करियर काउंसलिंग करेंगे।
- साथ ही, पूरे प्रदेश को 4 ज़ोन जयपुर ज़ोन (जयपुर एवं भरतपुर संभाग), कोटा ज़ोन (कोटा एवं उदयपुर संभाग), जोधपुर ज़ोन (जोधपुर एवं पाली संभाग), तथा बीकानेर ज़ोन (बीकानेर, चूरू एवं अजमेर संभाग) में बाँटकर 20 हेल्प डेस्क नंबर जारी किये गए हैं।
- इसके अलावा यूट्यूब पर करियर काउंसलिंग से संबंधित एक विस्तृत वीडियो तैयार कर जारी किया गया है।
- शिक्षा मंत्री डॉ. बी. डी. कल्ला ने बीकानेर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम के लोगो, ब्रोशर, बुकलेट और वीडियो का विमोचन किया।
- प्रदेश के उच्च माध्यमिक विद्यालयों के 15 हज़ार से अधिक पथ प्रदर्शक शिक्षक एवं विभाग के 500 से अधिक अधिकारी वीडियो कांफ्रेंस के जरिये कार्यक्रम से जुड़े।
- इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में 26 जून से प्रारंभ हुए नए शैक्षणिक सत्र के साथ ही ड्रॉप आउट बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिये स्कूल चलो अभियान (प्रवेशोत्सव) चलाया जा रहा है और अब 28 जून से 5 अप्रैल तक दसवीं पास करने वाले बच्चों का विषय चयन में मार्गदर्शन किया जाएगा।
- उन्होंने कहा कि पथ प्रदर्शक शिक्षक बच्चों को सही संकाय चयन के साथ दसवीं के बाद व्यवसायिक शिक्षा की भी जानकारी देंगें, जिससे वे कार्यशील जनसंख्या का हिस्सा बन सकेंगे।
- इस कार्यक्रम से विद्यार्थियों के कैरियर चयन की राह आसान होगी। विद्यार्थियों को कला, वाणिज्य एवं विज्ञान के अलावा ललित कला, संगीत, साहित्य, व्यवसायिक प्रशिक्षण, तकनीकी प्रशिक्षण की जानकारी भी दी जाएगी।
- 'डायल फ्यूचर'कार्यक्रम में संकाय चयन में मार्गदर्शन देने के साथ ही निकटतम विद्यालय की भी जानकारी दी जाएगी।
- इस कार्यक्रम के माध्यम से इसी सत्र में लगभग 9 लाख विद्यार्थियों के कॅरियर की राह को उज्ज्वल बनाने के लिये माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (आरएससीईआरटी), उदयपुर के साथ शिक्षा विभाग ने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई है।

नोट :

## उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री ने कोयम्बटूर में राजस्थानी संघ भवन का उद्घाटन किया

### चर्चा में क्यों ?

28 जून, 2023 को राजस्थान की उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत ने राजस्थानी संघ के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में तमिलनाडु राज्य के कोयम्बटूर ज़िले में नवनिर्मित राजस्थानी संघ भवन का उद्घाटन किया।

### प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री ने बताया कि यह भवन कोयम्बटूर ज़िले में रह रहे आमजन के लिये उपयोगी सिद्ध होगा। भवन निर्माण से शहर में रह रहे राजस्थानी प्रवासियों और यात्रा कर रहे राजस्थानियों को घर से दूर घर जैसा वातावरण मिल सकेगा।
- विदित है कि राजस्थान फाउंडेशन आयुक्त धीरज श्रीवास्तव निरंतर देश-विदेश में प्रवासी राजस्थानियों के लिये बेहतर कार्य कर रहे हैं।
- इस भवन के निर्माण से कोयम्बटूर शहर में रह रहे प्रवासी राजस्थानियों को विभिन्न सुविधाएँ उपलब्ध होंगी। साथ ही, राजस्थानी कला और संस्कृति से जुड़े कार्यक्रम, प्रदर्शनी भी आयोजित हो सकेंगी, जिससे सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा मिल सकेगा।

नोट :

# राजस्थान का एक स्टार्ट-अप यूथ को:लैब नेशनल इनोवेशन डायलॉग 2022 में विजेता बना

## चर्चा में क्यों ?

27 जून, 2023 को राजस्थान के जयपुर के आकाशदीय बंसल के स्टार्ट-अप को यूथ को:लैब नेशनल इनोवेशन डायलॉग इंडिया के 5वें संस्करण में विजेता घोषित किया गया।

## प्रमुख बिंदु

- विदित है कि कृषि, एड-टेक, महिलाओं की आजीविका, चक्रीय अर्थव्यवस्था और जैव विविधता में काम करने वाले 9 भारतीय राज्यों के बारह शीर्ष स्टार्ट-अप को यूथ को:लैब नेशनल इनोवेशन डायलॉग इंडिया के 5वें संस्करण में विजेता घोषित किया गया।
- विषयवस्तु 'युवाओं के लिये डिजिटल और वित्तीय साक्षरता'के अंतर्गत राजस्थान के आकाशदीप बंसल के स्टार्ट-अप 'एडुबिल्ड - युवाओं के लिये प्रयोग'को विजेता घोषित किया गया।
- प्रत्येक विषयगत क्षेत्र के विजेताओं को 5,000 डॉलर का सीड ग्रांट प्राप्त हुए; जबकि उपविजेता को 3,000 डॉलर प्राप्त हुए हैं। यह वित्त पोषण विजेताओं को अपने विचारों को मूर्त उत्पादों या सेवाओं में ढालने में मदद करेगा।
- विदित है कि यूथ को:लैब इंडिया 2022-23 ने 6 विषयगत क्षेत्रों- युवाओं के लिये डिजिटल और वित्तीय साक्षरता, जेंडर समानता और महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण, जैव विविधता संरक्षण पर केंद्रित फिनटेक समाधान विकसित करना, वित्त में प्रौद्योगिकियों के समाधानों के माध्यम से जैव विविधता के अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देना, अपसाइक्लिंग नवोन्मेषणों के माध्यम से चक्रीय अर्थव्यवस्था में तेजी लाना और लाइफ (पर्यावरण के लिये जीवन शैली) के लिये व्यवहारिक सुझाव पर ध्यान केंद्रित किया।
- यूथ को:लैब को 2019 में नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम) के साथ साझेदारी में भारत में लॉन्च किया गया था। वर्ष 2022-23 के संस्करण में देश भर के 28 राज्यों से 378 आवेदन प्राप्त हुए।
- आवेदनों में से 47 चयनित स्टार्ट-अप को एसडीजी इनोवेटर्स के लिये एक स्टार्ट-अप सपोर्ट प्लेटफॉर्म यूथ को:लैब स्प्रिंगबोर्ड प्रोग्राम के माध्यम से दो महीने के लिये विशेषज्ञों से प्रत्यक्ष परामर्श और क्षमता-निर्माण सत्र आयोजित किये गए। इन स्टार्ट-अप्स ने इसके बाद मई 2023 में एक प्रतिष्ठित जूरी के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत किये, जिसमें से 12 विजेताओं का चयन किया गया।
- अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम) के बारे में:
- स्व-रोज़गार और प्रतिभा उपयोग (सेतु) सहित एआईएम नवोन्मेषण और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने का भारत सरकार का प्रयास है।
- इसका उद्देश्य विशेष रूप से प्रौद्योगिकी-संचालित क्षेत्रों में विश्व स्तरीय नवोन्मेषण केंद्रों, बड़ी चुनौतियों, स्टार्ट-अप व्यवसायों और अन्य स्व-रोज़गार गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये एक मंच के रूप में कार्य करना है।
- यूएनडीपी इंडिया के बारे में:
  - यूएनडीपी ने 1951 से भारत में मानव विकास के लगभग सभी क्षेत्रों में काम किया है, जिसमें प्रणाली और संस्थागत मजबूती से लेकर समावेशी विकास और स्थायी आजीविका के साथ-साथ टिकाऊ ऊर्जा, पर्यावरण और लचीलापन शामिल है।
  - यूएनडीपी के कार्यक्रम भारत की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ उत्प्रेरक परिवर्तन के वैश्विक विजन को पूरी तरह से समेकित करते हैं। लगभग हर राज्य में 30 से अधिक परियोजनाओं के साथ, यूएनडीपी इंडिया अलग तरीके से विकास करने के लिये पारंपरिक मॉडलों को रूपांतरित कर सतत् विकास लक्ष्यों को अर्जित करने के लिये काम करता है।
- सिटी फाउंडेशन के बारे में:
  - सिटी फाउंडेशन विश्व में कम आय वाले समुदायों में आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देने और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिये काम करता है। यह ऐसे प्रयासों में निवेश करते हैं जो वित्तीय समावेशन को बढ़ाते हैं, युवाओं के लिये रोज़गार के अवसरों को उत्प्रेरित करते हैं और आर्थिक रूप से जीवंत समुदायों के निर्माण के लिये नए दृष्टिकोण की कल्पना करते हैं।
  - सिटी फाउंडेशन का 'परोपकार से भी अधिक'दृष्टिकोण मिशन को पूरा करने और विचार नेतृत्व और नवोन्मेषण को आगे बढ़ाने के लिये सिटी और उसके लोगों की प्रचुर विशेषज्ञता का लाभ उठाता है।

नोट :

- यूथ को:लैब के बारे में:
  - संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) और सिटी फाउंडेशन द्वारा 2017 में सह-निर्मित, यूथ को:लैब का उद्देश्य एशिया-प्रशांत क्षेत्र के देशों के लिये युवाओं को सशक्त बनाने और उनमें निवेश करने के लिये एक साझा एजेंडा स्थापित करना है ताकि वे नेतृत्व, सामाजिक नवोन्मेषण और उद्यमिता के माध्यम से सतत् विकास लक्ष्य (एसडीजी) के कार्यान्वयन में तेजी ला सकें।
  - 2017 से यूथ को:लैब ने एशिया और प्रशांत क्षेत्र के 28 देशों और क्षेत्रों में युवा आकांक्षी और प्रेरक सामाजिक उद्यमियों की सहायता की है।

## जोधपुर एवं कोटा में स्थापित होंगे साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेंटर

### चर्चा में क्यों ?

28 जून, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के जयपुर, जोधपुर एवं कोटा मेडिकल कॉलेजों में साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेंटर स्थापित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की है।

### प्रमुख बिंदु

- साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेंटर स्थापित करने के साथ-साथ इस हेतु आवश्यक फर्नीचर एवं उपकरणों के क्रय की मंजूरी भी दी गई है।
- प्रस्ताव के अनुसार, यह सेंटर चिकित्सा महाविद्यालय/चिकित्सालय में उपलब्ध स्थान पर संचालित किये जाएंगे। प्रत्येक संस्थान के लिये 3 क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट, 6 काउंसलर्स, 4 वार्ड बॉय/सिक्योरिटी गार्ड/अटेंडेंट तथा 2 मशीन विद मैन की सेवाएँ अनुबंध पर लेने की स्वीकृति भी प्रदान की गई है।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने बजट वर्ष 2023-24 में इस संबंध में घोषणा की थी।

## प्रदेश में तटरक्षक मेडल से अलंकृत सैनिकों को भी मिलेगा सुविधाओं का लाभ

### चर्चा में क्यों ?

28 जून, 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में तटरक्षक मेडल से अलंकृत सैनिकों को भी राजस्थान शौर्य पुरस्कार (नकद पुरस्कार और भूमि अनुदान) नियम 1966 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा देय सुविधाओं का लाभ देने के संबंध में आवश्यक स्वीकृति प्रदान की है।

### प्रमुख बिंदु

- प्रस्ताव के अनुसार, राष्ट्रपति तटरक्षक मेडल (वीरता) धारकों को 6 लाख रुपए नकद एवं 25 बीघा सिंचित भूमि या भूमि के एवज में 25 लाख रुपए नकद दिये जाएंगे।
- इसी प्रकार, तटरक्षक मेडल (वीरता) धारकों को 30 हज़ार रुपए नकद एवं 25 बीघा सिंचित भूमि या भूमि के एवज में 25 लाख रुपए नकद राशि दी जाएगी। पदकधारकों को ये लाभ 26 जनवरी, 1990 से देय होंगे।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने बजट वर्ष 2023-24 में इस संबंध में घोषणा की थी।

नोट :